ELITE IAS

समसामयिकी

जुलाई - 2018

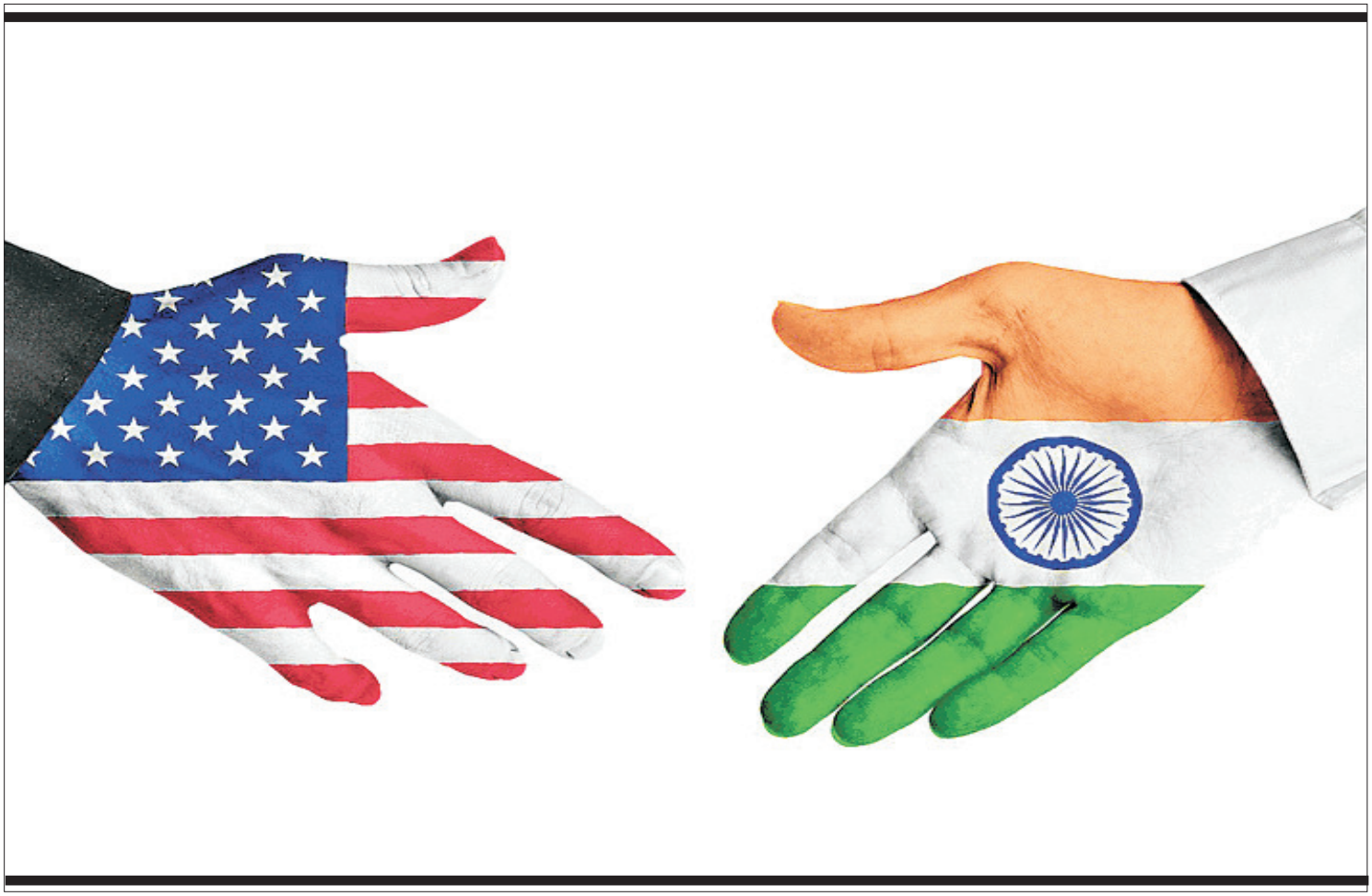

8899999931/34

A-1 Chandra House, Top Floor, (Opp. ICICI Bank), Mukherjee Nagar, Delhi-09

ELITE IAS

Our Courses

For Civil Services Preparation

CLASSROOM PROGRAM

Hindi / English

Upgraded Foundation Course
General Studies

ONLINE COURSES

General Studies Video Classes
(Interactive)

ALL INDIA TEST SERIES

English / Hindi

General Studies
Prelims + Mains + Essay

CORRESPONDENCE COURSES

General Studies Pre. & Mains
(Interactive)

Index

आलेख

1. विदेश नीति की कड़ी अग्निपरीक्षा 1-3

कला, संस्कृति, समाज एवं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

2. भारत को 37वां विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिला 4-9

3. थॉमसन रायटर्स सर्वेक्षण: भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश 9-10

4. इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018: सूरत 'सिटी अवार्ड' के लिए चुना गया 10-12

5. सोशल मीडिया पर महिलाओं को अभद्र रूप में पेश करने से रोकने के लिए एजेंसी बनाने को मंजूरी 12-13

6. भारत में मातृ मृत्यु दर में 22 प्रतिशत की कमी 13-14

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

7. पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति 15-16

8. 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' का गठन 16-17

9. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी 17-18

10. यूजीसी को समाप्त करके नया आयोग बनाने हेतु प्रस्ताव 18-19

11. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'जेलों में महिलाएं' विषय पर रिपोर्ट जारी की 19-21

12. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान टेक-थॉन के आयोजन की घोषणा 21-23

अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत एवं विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

13. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018: भारत 137 वें स्थान पर 24-24

14. जी 7 सम्मेलन: व्यापार में संरक्षणवाद के विरोध का संकल्प लिया गया 25-25

15. अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद छोड़ने की घोषणा की 25-26

16. मॉरीशस 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा 27-27

17. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' में शामिल किया 28-29

18. नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी 29-30

19. SIPRI रिपोर्ट: केवल दो देशों के पास विश्व के 92% परमाणु हथियार 30-31

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

20.	'सौर चरखा मिशन'	32-33
21.	'सूर्य शक्ति योजना'	33-33
22.	आरबीआई ने बॉन्ड में विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी	34-35
23.	आरबीआई ने 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' आयोजित किया	35-36
24.	केंद्र सरकार ने 'कृषि कल्याण अभियान' आरंभ किया	36-37
25.	द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति, 2018-19	37-38

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा एवं स्वास्थ्य

26.	केंद्र सरकार ने 'गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक' स्थापित करने को मंजूरी दी	39-40
27.	भारत ने 'अग्नि-5' मिसाइल का सफल परीक्षण किया	40-41
28.	भारत में ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबन्ध प्रभावी	41-42
29.	सांगली की हल्दी को जीआई टैग हासिल हुआ	42-43
30.	राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी	44-44
31.	नया रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र का उद्घाटन	45-46
32.	3000 अतिरिक्त अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा	46-47
33.	अमेरिकी सरकार ने छह लड़ाकू अपाचे हेलिकॉप्टर की खरीद को मंजूरी प्रदान की	48-48

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

34.	जलवायु परिवर्तन भारत की जीडीपी को प्रभावित कर सकता है: विश्व बैंक	49-50
35.	स्वच्छ भारत मिशन: केंद्र सरकार ने 10 नए स्वच्छ दर्शनीय स्थलों की घोषणा की	51-52
36.	केंद्र सरकार बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ मिलकर काम करेगी	52-53
37.	समुद्र में गंदगी के लिए गंगा सहित विश्व की 10 नदियां जिम्मेदार: रिपोर्ट	53-54
38.	समग्र जल प्रबंधन रिपोर्ट	54-55
39.	विश्व महासागर दिवस	56-56

40.	पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक: भारत 177वें स्थान पर	57-58
41.	विश्व पर्यावरण दिवस : 2018	58-59

अन्य `बरें

42.	12वां सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया	60-60
43.	लुईस हैमिल्टन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता	60-60
44.	नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस	60-61
45.	अनुकृति वास ने जीता मिस इंडिया 2018 का खिताब	61-61
46.	विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2018 मनाया गया	61-61
47.	इवान ड्यूक कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित	61-61
48.	विश्व रक्तदान दिवस	62-62
49.	अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस: 2018	62-63
50.	राफेल नडाल ने 11वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता	63-63
51.	महेश कुमार जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त	63-63

ELITE IAS

आलेख

विदेश नीति की कड़ी अग्निपरीक्षा

हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू डायलॉग के स्थगित होने और ट्रेड-वार को लेकर अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती रस्साकशी के कारण भारत-अमेरिका संबंध में फिर से तनाव के संकेत मिल रहे हैं। जहां टू प्लस टू डायलॉग के स्थगन के पीछे अमेरिका ने कोई वजह नहीं बताई, वहीं इस व्यापार-युद्ध की जद में भारत के भी आने की आशंका बढ़ गई है। इससे इतर पिछले महीने जून में सिंगापुर में संपन्न शांगरी-ला वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की विदेश नीति पर दिए गए बयान ने भी भारत-अमेरिका संबंध में बढ़ती असहमति की तरफ इशारा किया था। प्रधानमंत्री ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भारत और अमेरिका के 'साझा दृष्टिकोण' की बात की, जो कि अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटिस द्वारा इसी समारोह में दिए गए बयान से काफी अलग था। लिहाजा दोनों देशों के बीच बढ़ती असहमति इनके रिश्तों में मतभेद के संकेत तो दे ही रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की साख बढ़ाने की कोशिशों से भी कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है।

मतभेद के बिंदु

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध में पिछले कुछ दिनों से तनाव के संकेत मिल रहे हैं और टू प्लस टू डायलॉग का स्थगन इसी कड़ी की बानगी प्रतीत होती है। अगर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने शांगरी-ला डायलॉग में इसे एक प्राकृतिक भू-क्षेत्र के रूप में संबोधित किया, न कि रणनीतिक, जबकि अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने हिंद-प्रशांत को सैन्य अधिकार के लिए व्यापक सुरक्षा रणनीति का क्षेत्र बताया। इससे साफ होता है कि अमेरिका इस क्षेत्र को रणनीतिक अथवा सामरिक क्षेत्र के रूप में बनाए रखना चाहता है, जबकि भारत सिर्फ व्यापार के नजरिये से इस क्षेत्र को विकसित करना चाहता है। मोदी ने चीन के साथ संबंध सुधार तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली के लिए अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों को एक समान रूप में संदर्भित किया है, जबकि अमेरिका द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों का मुकाबला करने की बात कही गई है। जाहिर है अमेरिका का यह प्रयास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव को निमंत्रण जैसे होगा। अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड-वार इसी का दूसरा पहलू हो सकता है।

भारत की भूमिका

दरअसल हिंद-प्रशांत आर्थिक गलियारे की अवधारणा भारत-अमेरिका सामरिक वार्ता के दौरान प्रस्तुत की गई थी। यह अवधारणा एशिया के नए विकास क्षेत्रों में अमेरिका की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए एक नई संभावना को तलाशने की कोशिश थी। हिंद-प्रशांत शब्द पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया से पूर्वी एशिया तक फैली पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर की समुद्री जगह को संदर्भित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक देश की न बता कर सभी देशों की बताई है। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री का यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को संदेश है कि बिना किसी वजह के वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कोई तनाव पैदा न करे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

दूसरी ओर एच-1बी पेशेवर वीजा में प्रस्तावित कटौती और एच 4 वीजा को रद करने की अमेरिकी कोशिश भी भारत-अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करती हैं। यह जानना बेहद जरूरी है कि एच-1बी वीजा भारतीय पेशेवरों के बीच बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि लाखों भारतीय अभी अमेरिका में काम कर रहे हैं। जहां तक एच4 वीजा का सवाल है तो यह एच-1बी वीजा धारकों के जीवन साथियों को जारी किया जाता है। ऐसे समय में जब लाखों भारतीय अमेरिका में रोजगार पा रहे हैं तब ट्रंप प्रशासन के इस प्रस्ताव से अमेरिका में रह रहीं हजारों भारतीय महिलाएं प्रभावित होंगी। अगर अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर नए टैरिफ की बात करें तो इससे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेशी इस्पात पर 25 फीसद और एल्युमीनियम पर 10 फीसद की दर से शुल्क लगाने का फैसला न केवल भारत के स्थानीय बाजारों पर असर डालेगा, बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतों को भी बढ़ाएगा। जाहिर है इससे भी रिश्ते में तल्खी बढ़ने की आशंका है।

एक और बात जो महत्वपूर्ण है वह यह कि हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल मामले ने भी भारत और अमेरिका के बीच विवाद को बढ़ा दिया। हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत ने टैरिफ को 75 फीसद से कम कर 50 फीसद जरूर किया, लेकिन इसके बावजूद वाशिंगटन के अधिकारियों को आपत्ति है। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका इंडियन रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के आयात पर शून्य टैरिफ लगाता है। जाहिर है मोदी प्रशासन की भी कुछ कोशिशें तनाव को बढ़ा रही हैं।

भारत की भूमिका

दरअसल दोनों देशों के बीच बढ़ने वाला यह तनाव एकतरफा नहीं है। भारत द्वारा भी उठाए गए कई ऐसे कदम हैं जिन पर अमेरिका ने एतराज जताया है। भारत ने इस वर्ष जून में अमेरिका और जापान के साथ समुद्री अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसके विपरीत रूस तथा चीन की अगुआई वाले शंघाई सहयोग संगठन के देशों के साथ किंगदाओ में होने वाले सैन्य अभ्यास के आयोजन में शामिल होने की भारत की स्वीकृति से भी ट्रंप प्रशासन चिंतित है। साथ ही डेयरी और पोर्क उत्पादों के निर्यात के प्रतिरोध पर भारत के टैरिफ और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय सर्वर पर डाटा स्थानीयकरण के नियम लागू करना, ऐसे प्रयास हैं जो तनाव के कारण बन रहे हैं।

इसके अलावा यदि अनौपचारिक और औपचारिक शिखर सम्मेलन के साथ-साथ शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और जी-20 बैठकों की बात की जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वर्ष के अंत तक चार-पांच बार मिल चुके होंगे। इसके विपरीत भारत-अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता को निर्धारित करने में लगभग छह माह का वक्त लग गया था। हाल के महीनों में व्यापार संरक्षणवाद के नाम पर दोनों देश कई दफा एक-दूसरे को विश्व व्यापार संगठन में ले गए हैं और यह भी भारत और अमेरिका के बीच विरोध का बड़ा मुद्दा है। जाहिर है ये ऐसे पहलू हैं जिन पर भारत को भी मंथन करने की जरूरत है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

टू प्लस टू डायलॉग

जब दो देशों के बीच एक साथ ही दो-दो मंत्रिस्तरीय या सचिवस्तरीय वार्ताएं आयोजित की जाती हैं तो इसे टू प्लस टू वार्ता मॉडल का नाम दिया जाता है। गौरतलब है कि यह पहला मौका था जब मंत्री स्तर पर भारत किसी देश के साथ टू प्लस टू डायलॉग जैसी पहल को अंजाम देने की राह पर था। हालांकि सचिव स्तर पर भारत ऐसी वार्ताएं दूसरे देशों के साथ कर चुका है। भारत और अमेरिका के बीच संवाद को नया रूप देने के लिए नियमित वार्ता का एक ऐसा ढांचा विकसित करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत हो सके। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी था कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में भारत-अमेरिका मिलकर अपनी भूमिका निभाएं। प्रस्तावित संरचना के तहत भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू संवाद व्यवस्था में नियमित रूप से दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश सचिवों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने की योजना थी।

आगे की राह

गौरतलब है कि पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत-अमेरिकी संबंध हमेशा से ही सहयोगी बने रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में यह संबंध लेन-देन की नीति पर निर्भर कर रहा है। इसी कारण भारत-अमेरिका के बीच अलग-अलग मुद्दों पर असहमति देखी जा रही है। इन असहमतियों के कारण ही दोनों देशों के रिश्ते में अस्थिरता आ रही है।

लेकिन सवाल यह भी है कि इससे इतर दूसरे मुद्दों पर अगर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनती है तो दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक हित किस हद तक प्रभावित होंगे? दरअसल नए अमेरिकी कानून तथा रूस, ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध भारत-अमेरिकी संबंधों के लिए बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के मामले में भारतीय संस्थाओं को तो रोक ही रहा है, साथ ही रूस के साथ व्यापार करने पर भी इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है अमेरिका भारत के हितों की अनदेखी कर रहा है। एक ओर रूस के साथ जहां भारत का 70 सालों का गहरा रिश्ता है, वहीं मौजूदा वक्त में भारत ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात करता है। जाहिर है ये प्रतिबंध भारत का ईरान और रूस के साथ संबंधों को एक चुनौतीपूर्ण चौराहे पर ले जाएंगे। हालांकि भारत ने कई बार संकेत दिए हैं कि वह अमेरिकी नाराजगी के बावजूद ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। इसी तरह मौजूदा ट्रेड-वार पर भी भारत ने अमेरिका के सामने नहीं झुकने के संकेत दिए हैं।

बहरहाल अमेरिका और भारत दोनों देशों को टू प्लस टू संवाद जैसी व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि निरंतर संवाद के जरिये हिंद-प्रशांत जैसे मुद्दे सहित अन्य मसलों को सुलझाने के प्रयास किए जा सकें। भारत को भी वह आगे बढ़ कर अमेरिका के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा प्रधानमंत्री की विदेश नीति को सुधारने की कोशिशें सार्थक नहीं हो पाएंगी। जाहिर है तब मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों के घेरे में आ जाएगी।

हाल में भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू डायलॉग अचानक स्थगित हो गया। वहीं चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार की तल्खी भी बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को भी आड़े हाथों ले चुके हैं। इससे दुनिया में व्यापार युद्ध के और भड़कने की आशंका है। इससे किसी का भला नहीं होने वाला। बेहतर हो कि इसके लिए मध्य मार्ग निकाला जाए जिसमें कोई भी पक्ष ठगा महसूस न करे। इसके लिए अमेरिका और भारत को निरंतर संवाद कर विवाद सुलझाने होंगे तभी परस्पर प्रगति की राह खुलेगी।

कला, संस्कृति, समाज , तथा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

भारत को 37वां विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिला

चर्चा में क्यों?

☞ हाल ही में भारत के 'मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स' को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित किया गया। यह निर्णय बहरीन के मनामा में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 42वें सत्र में लिया गया।

मुख्य तथ्य:

- एलिफेंटा गुफाओं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन (विक्टोरिया टर्मिनस) के बाद विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जाना मुंबई को मिला तीसरा ऐसा सम्मान है।
- दक्षिण मुंबई में स्थित विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको के भवनों को मियामी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी भवन श्रृंखला में शामिल किया जाता है।
- अहमदाबाद विश्व धरोहर शहर घोषित किया जाने वाला भारत का पहला शहर था।
- एलिफेंटा गुफाओं को वर्ष 1987 और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2004 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- देश में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 37 हो गई है जिनमें 29 सांस्कृतिक, सात प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल हैं।
- विश्व धरोहर समिति में सभी 21 देशों ने नामांकन का समर्थन किया जो बहुत दुर्लभ है।

विश्व धरोहर:

- युनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों (जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, या शहर इत्यादि) को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं।
- यह समिति इन स्थलों की देखरेख युनेस्को के तत्वाधान में करती है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
- वर्ष 2006 तक पूरी दुनिया में लगभग 830 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है जिसमें 644 सांस्कृतिक, 24 मिले-जुले और 138 अन्य स्थल हैं।
- प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती है, जिस देश में वह स्थल स्थित हो; परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे आनेवाली पीढ़ियों के लिए और मानवता के हित के लिए इनका संरक्षण करें।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

युनेस्को

- यूनेस्को (UNESCO) श्संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघुरूप है।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है।
- इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है।
- संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवम्बर 1945 को हुआ था।
- इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए।
- यूनेस्को के 195 सदस्य देश हैं और सात सहयोगी सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है, यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश के कई ऐतिहासिक इमारत और पार्क शामिल हैं।

भारत के 37 विश्व धरोहर स्थल

विश्व धरोहर स्थल	विवरण
आगरा का किला	आगरा का किला आगरा का किला को "लाल किला" भी कहते हैं, यहा आगरा शहर में स्थित है। वर्ष 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
अंजता की गुफाएं	भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पड़ने वाली अजंता की गुफाओं में चट्टानों की बनी करीब 30 बौद्ध गुफा स्मारक हैं। अजंता की गुफाएं वर्ष 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में हैं।
एलोरा की गुफाएं	एलोरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के 29 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित एक परातात्विक स्थल हैं। एलोरा की गुफाओँ को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
ताज महल	यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 17 हेक्टेयर जमीन पर बने मुगल गार्डन के भीतर बना ताज महल यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1632 ई. में शुरु हुआ था और 1648 में बन कर यह तैयार हो गया था। वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह	अभयारण्यों का यह समूह, पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था। वर्ष 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

❑ **सूर्य मंदिर कोणार्क**	भारत की विरासत में वास्तुकला का चमत्कार, कोणार्क का सूर्य मंदिर, आमतौर पर जिसे कोणार्क नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी राज्य ओडीशा (पहले उड़ीसा कहा जाता था) में स्थित है और पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र में से एक है। वर्ष 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान**	यह विश्व विरासत स्थल है। यहां एक-सींग वाले गैंडे की दो-तिहाई आबादी पाई जाती है। विश्व के संरक्षित इलाकों में से काजीरंगा में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान**	भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाने वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के दो सबसे ऐतिहासिक शहरों आगरा और जयपुर के बीच है. वर्ष 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **मानस वन्यजीव अभयारण**	यह असम राज्य के भूटान-हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में बसा है। यह अनूठे जैवविविधता और परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **गोवा के चर्च और आश्रम (कॉन्वेंट)**	भारत के पश्चिमी तट पर स्थित इस राज्य के वेल्हा (पुराने) गोवा के चर्च और आश्रम पुर्तगाली शासन के युग से ही हैं। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी का निर्माण बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में बनवाया था। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **हंपी में स्मारकों का समूह**	हंपी की सादगी और भव्यता में मुख्य रूप से अंतिम महान हिन्दू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य (14वीं-16वीं शती ई.) की राजधानी के अवशेष मिलते हैं। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **खजुराहो के स्मारकों का समूह**	खजुराहो के मंदिर (मध्यप्रदेश में) देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 900 और 1130 ई. के बीच करवाया था। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **एलिफेंटा की गुफाएं**	एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में एलिफेंटा द्वीप या घरापुरी पर स्थित मूर्तियों की गुफाओं की श्रृंखला है। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

❑ **महान चोल मंदिर**	महान चोल मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा करवाया गया था। यह पूरे दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों में बना हुआ है। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **पत्तदकल के स्मारकों का समूह**	कर्नाटक में पत्तदकल उद्धारक कला का उत्कृष्ट नमूना है। इनका निर्माण चालुक्य वंश के दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया गया था। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान**	विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुन्दरबन, भारत और बांग्लादेश के 10,200 वर्ग किमी में फैले सदाबहार वन में है। भारत की सीमा में पड़ने वाला वन का हिस्सा सुन्दरबन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान**	यह उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की पहाड़ी पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
❑ **सांची का बौद्ध स्तूप**	भारत में बौद्ध पर्यटकों के लिए सांची काफी लोकप्रिय स्थान है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। यूनेस्को ने 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **हुमायूं का मकबरा, दिल्ली**	दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा पहला भव्य शाही मकबरा है जो मुगल वास्तुकला और स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा 21.60 हेक्टेयर में बना है। यूनेस्को ने 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **कुतुब मीनार, दिल्ली**	कुतुबमीनार दिल्ली के दक्षिण में कुछ किलोमीटर दूर करीब 13वीं सदी में बना था। यूनेस्को ने 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **भारत के पहाड़ी रेलवे**	भारत के पहाड़ी रेलवे में तीन रेलवे हैंख्र दार्जीलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरि माउंटेन रेलवे, और कालका शिमला रेलवे है। यूनेस्को ने 1999 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **बोध गया का महाबोधी मंदिर परिसर**	महाबोधी मंदिर परिसर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया पहला मंदिर है। यूनेस्को ने 2001 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **भीमबेटका पाषाण आश्रय**	यह पांच पाषाण आश्रयों का समूह है और 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

❑ **चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व उद्यान**	पावागढ़ पहाड़ी के शीर्ष पर बना कालिकामाता मंदिर को महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है और यहां पूरे वर्ष श्रद्धालु आते रहते हैं। यूनेस्को ने 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पहले विक्टोरिया टर्मिनस)**	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे), अरब सागर के तट को छूते भारत के पश्चिमी हिस्से में मुंबई में है। यूनेस्को ने 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **लाल किला परिसर (दिल्ली)**	वर्ष 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और शाहजहांबाद शहर की नींव रखी। यूनेस्को ने 2007 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **जंतर-मंतर, जयपुर**	जयपुर का जंतर मंतर खगोलीय प्रेक्षण स्थल है जिसका निर्माण 18वीं सदी के आरंभ में किया गया था। यूनेस्को ने 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **पश्चिमी घाट**	पश्चिमी घाट तापी नदी की चोटी से निकलकर कन्याकुमारी की गुफा तक 1600 किमी की दूरी तक फैला है इसकी औसत उंचाई 1200 मीटर है। यूनेस्को ने 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **राजस्थान के पहाड़ी किले**	राजस्थान राज्य में स्थित सिलसिलेवार स्थान। इसमें छह आलीशान किले-चितौड़गढ़, कुंभलगढञ, सवाई माधोपुर, झालवार, जयपुर और जैसलमेर हैं। यूनेस्को ने 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **रानी-की-वाव (रानी की बावड़ी) पाटण, गुजरात**	सरस्वती नदी के किनारे पर बनी रानी-की-वाव का निर्माण आरंभ में 11वीं शताबदी में एक राजा के स्मारक के तौर पर कराया गया था। यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान**	यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लु जिले में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **नालंदा महाविहार (नालंदा विश्वविद्यालय)**	बिहार में नालंदा पुरातत्व साइट सीखने का एक केंद्र और 13 वीं सदी के लिए 3 शताब्दी ईसा पूर्व से एक बौद्ध मठ था। यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
❑ **कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान**	कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- **कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़,** चंडीगढ़ की राजधानी परिसर सहित कई देशों भर ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प काम आधुनिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में एक विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।
- **अहमदाबाद** गुजरात की 606 साल पुरानी सिटी अहमदाबाद अब विश्व धरोहर सिटी के नाम से जानी जाएगी।
- **मुंबई की 'विक्टोरियन गोथिक' और 'आर्ट डेको'** मुंबई की शविक्टोरियन गोथिक' और 'आर्ट डेको' यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने 2018 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।

स्रोतः द हिंदू, विकिपीडिया

थॉमसन रायटर्स सर्वेक्षण:भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश

चर्चा में क्यों?

- महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन द्वारा वैश्विक सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया है।
- सर्वेक्षण से पता चलता है कि युद्धग्रस्त सीरिया और अफगानिस्तान भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं. सोमालिया और सऊदी अरब में भी सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं के लिए भारत से बेहतर स्थिति है।

सर्वेक्षण के प्रमुख तथ्य

- सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मानव तस्करी, यौन हिंसा, सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं के कारण और महिलाओं को यौन अपराधों में धकेलने के कारण यह सबसे खतरनाक देश है।
- थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन के सर्वे में 193 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें से महिलाओं के लिए बदतर शीर्ष 10 देशों का चयन किया गया।
- इन टॉप 10 देशों में भारत की स्थिति सबसे बदतर है और इसे पहले स्थान पर रखा गया है।
- सूची में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान और सीरिया दूसरे और तीसरे, सोमालिया चौथे और सउदी अरब पांचवें स्थान पर हैं।
- शीर्ष 10 देशों में अमेरिका 10वें स्थान पर है अर्थात वह भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, जबकि पहले नौ स्थानों पर एशियाई देश ही शामिल हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यह सर्वेक्षण 26 मार्च से 04 मई के बीच कराया गया, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र को शामिल किया गया। इसमें विशेषज्ञों से महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और उन्हें यौन संबंधों के लिए मजबूर करने को लेकर सवाल किए गए।
- इसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया के पेशेवर, शिक्षाविद, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन के लोग, नीति निर्माता, विकास विशेषज्ञ और सामाजिक टिप्पणीकार आदि शामिल थे.फाउंडेशन ने सात साल पहले 2011 में भी ऐसा ही सर्वेक्षण कराया था, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भारत को चौथे स्थान पर रखा गया था।

स्रोतः द हिंदू

इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018: सूरत 'सिटी अवार्ड' के लिए चुना गया

चर्चा में क्यों?

- 'इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड' 2018 के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज गति प्रदर्शित करने पर सूरत स्मार्ट सिटी को 'सिटी अवार्ड' के लिए चुना गया।
- तीन वर्गों अर्थात परियोजना पुरस्कार, नवोन्मेषी विचार पुरस्कार एवं सिटी अवार्ड में 9 पुरस्कारों की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत घोषणा की गई है।

1. **सिटी अवार्डः**

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष रूप से शहरी पर्यावरण, परिवहन एवं गंत्यात्मकता तथा टिकाऊ समेकित विकास के वर्गों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज गति प्रदर्शित करने के लिए सूरत स्मार्ट सिटी को सिटी अवार्ड के लिए चुना गया।

2. **नवोन्मेषी विचार पुरस्कारः**

नवोन्मेषी विचार पुरस्कार किसी परियोजना/विचार, विशेष रूप से टिकाऊ समेकित विकास की दिशा में उनके नवोन्मेषी, बॉटम-अप एवं रूपांतरकारी दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ग में संयुक्त विजेता अपने समेकित कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (आईसीसीसी) के लिए भोपाल तथा सुरक्षित एवं भरोसेमंद अहमदाबाद (एसएएसए) परियोजना के लिए अहमदाबाद रहे।

3. **परियोजना पुरस्कारः**

परियोजना पुरस्कार सात वर्गों में सर्वाधिक नवोन्मेषी एवं सफल परियोजनाओं को दिया जाता है, जो 01 अप्रैल 2018 तक पूरी हो चुकी है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

चुनी गई परियोजनाएं:

क्र.सं.	श्रेणी	परियोजना का नाम
1.	अभिशासन	पुणे से पीएमसी केयर
2.	निर्मित पर्यावरण	पुणे से स्मार्ट प्लेस मेकिंग
3.	सामाजिक पहलू	एनडीएमसी एवं जबलपुर से स्मार्ट क्लास रूम, विशाखापत्तनम से स्मार्ट कैम्पस, पुणे से लाईट हाउस
4.	संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था	भोपाल से बी नेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर एवं जयपुर से राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का संरक्षण
5.	शहरी पर्यावरण	भोपाल, पुणे, कोयम्बटूर से पब्लिक बाईक शेयरिंग एवं जबलपुर में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र
6.	परिवहन एवं गंत्यात्मकता	अहमदाबाद एवं सूरत से समेकित पारगमन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस)
7.	जल एवं स्वच्छता	अहमदाबाद से एससीएडीए के माध्यम से स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट

इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड:

- इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड शहरों, परियोजनाओं एवं नवोन्मेषी विचारों को पुरस्कृत करने, नगरों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 जून 2017 को आरंभ किया गया था।
- योग्य प्रतिभागियों में केवल स्मार्ट सिटी शामिल थे जहां संबंधित यूएलबी/स्मार्ट सिटी एसपीवी को प्रस्ताव पेश करना था।
- सिटी अवार्ड पर फैसला 02 मई 2018 (पुरस्कार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) को उनके पुरस्कार स्कोर एवं साप्ताहिक रैंकिंग पर नगरों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट, एशियाई विकास बैंक एवं एनआईयूए के अंतर्राष्ट्रीय/बहु-स्तरीय विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति ने नवोन्मेषण, प्रभाव एवं प्रतिकृति/अनुमापकता पर आधारित प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया।
- नगर को कोई प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं है।
- प्रोजेक्ट अवार्ड' एवं 'नवोन्मेषी विचार अवार्ड' के लिए विविध प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और मूल्यांकन के लिए परियोजना कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में शिलांग का चयन

- मेघालय की राजधानी शिलांग का चयन 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है. शिलांग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के आकलन के बाद ही इस शहर का चयन किया गया है।
- अब तक संबंधित प्रतिस्पर्धा के चार दौर में 99 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था. इससे पहले जनवरी 2016 में 20 शहरों, मई 2016 में 13 शहरों, सितम्बर 2016 में 27 शहरों, जून 2017 में 30 शहरों और जनवरी 2018 में 9 शहरों का चयन किया गया था।
- शिलांग के चयन के साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अंतिम रूप से चयनित 100 स्मार्ट सिटी में कुल प्रस्तावित निवेश 2, 05,018 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

स्रोतः द हिंदू

सोशल मीडिया पर महिलाओं को अभद्र रूप में पेश करने से रोकने के लिए एजेंसी बनाने को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने परंपरागत और आधुनिक सोशल मीडिया में महिलाओं को अभद्र और अशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी बनाने का निर्णय किया है।
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 04 जून 2018 को 'महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम (आईआरडब्ल्यूए) 1986' में संशोधन करने की संसदीय समिति की सिफारिश मंत्रालय ने स्वीकार कर ली है।

एजेंसी का स्वरुप

- इस अधिनियम में बदलाव एवं एजेंसी के गठन के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसे लेकर वर्ष 2012 में राज्यसभा में एक संशोधित विधेयक पेश किया गया था जिसे बाद में संसदीय स्थायी समिति में भेज दिया गया था।
- इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- इसके अलावा महिलाओं के मुद्दों पर कार्यरत किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को भी इसका सदस्य बनाया जायेगा।
- यह केंद्रीय एजेंसी किसी कार्यक्रम, विज्ञापन और प्रकाशन किसी भी महिला की अभद्र प्रस्तुति से संबंधित शिकायतों को सुन सकेगी और जांच कर सकेगी।

इस अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है:

- विज्ञापन की परिभाषा में संशोधन में डिजिटल स्वरूप या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप अथवा होर्डिंग या एसएमएस, एमएमएस आदि के जरिए विज्ञापन को शामिल किया जाएगा।
- वितरण की परिभाषा में संशोधन में प्रकाशन, लाइसेंस या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर अपलोड करने अथवा संचार उपकरण शामिल किए जाएंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- प्रकाशन शब्द को परिभाषित करने के लिए नई परिभाषा को जोड़ना।
- धारा-4 में संशोधन से कोई भी व्यक्ति ऐसी सामग्री प्रकाशित या वितरित करने के लिए तैयार नहीं कर सकता, जिसमें महिलाओं का किसी भी तरीके से अशिष्ट निरूपण किया गया हो।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रदत्त दंड के समान दंड के प्रावधान।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनडब्ल्यूसी) के तत्वाधान में केन्द्रीकृत प्राधिकरण का गठन. इस प्राधिकरण की अध्यक्ष एनडब्ल्यूसी की सदस्य सचिव होंगी और इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे तथा महिला मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव रखने वाली एक सदस्य होगी।
- केन्द्रीयकृत प्राधिकरण को प्रसारित या प्रकाशित किए गए किसी भी कार्यक्रम या विज्ञापन से संबंधित शिकायत प्राप्त करने और महिलाओं के अशिष्ट निरूपण से जुड़े सभी मुद्दों की जांच करने का अधिकार होगा।

स्रोतः द हिंदू

भारत में मातृ मृत्यु दर में 22 प्रतिशत की कमी

चर्चा में क्यों?

- भारत में वर्ष 2013 से मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में रिकार्ड 22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है. यह जानकारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) ने 06 जून 2018 को अपने द्वारा एकत्र किए गए डाटा के आधार पर दी है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-13 में मातृ मृत्यु दर जहां 167 था वहीं वो वर्ष 2014-16 में घटकर 130 हो गया। एमएमआर को 100,000 जीवित जन्मों की मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

मुख्य तथ्यः

- यह गिरावट 'इंपावर्ड एक्शन ग्रुप' (ईएजी) राज्यों (246 से घटकर 188) में सबसे महत्वपूर्ण है. जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और असम शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत की कमी के साथ राज्यों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है।
- मातृ मृत्यु दर पर रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिणी राज्यों में यह 93 से घटकर 77 और अन्य राज्यों में 115 से घटकर 93 रह गई है।
- वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2016 में प्रसव के समय मां की मुत्यु के मामलों में करीब 12 हजार की कमी आई है और ऐसी स्थिति में माताओं की मृत्यु का कुल आंकड़ा पहली बार घटकर 32 हजार पर आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में वर्ष 2013 की तुलना में अब हर दिन 30 ज्यादा गर्भवती महिलाओं को बचाया जा रहा है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)

- भारत में नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) देश और प्रमुख राज्यों के लिए मृत्यु दर के प्रत्येक आकलन प्रदान करने का एक मात्र स्रोत है।
- यह आकलन 1997 से प्रदान किये जा रहे हैं। मातृ मुत्यु दर संबंधी आंकडे मौखिक शव-परीक्षा (ऑटाप्सी) के आधार पर तैयार किये जाते हैं, जो एसआरएस के अधीन बताई गयी सभी मरने वालों के बारे में जानकारी के आधार पर क्रियान्वित की जाती है।
- त्वरित आकलन तैयार करने के लिए तीन वर्षों के आकडों को जोड़कर मातृ मृत्यु अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- विदित हो कि नमूना पंजीकरण प्रणाली बड़े पैमाने पर होने वाला जनसंख्या सर्वेक्षण है जो राष्ट्रीय स्तर पर जन्मदर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन तथा मृत्यु संबंधी संकेतकों के विश्वनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करता है।
- जमीनी जांच में चुनी हुई इकाइयों में पार्ट टाइम गणनाकारों आमतौर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अध्यापकों द्वारा चुनी हुई नमूना इकाइयों में जन्म और मृत्यु की लगातार गिनती की जाती है और एसआरएस के सुपरवाइजर हर छह महीने में स्वतंत्र सर्वेक्षण करते हैं।
- इन दो स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों को मिलाया जाता है. बेमेल और आंशिक रूप से मेल खाने की स्थिति में इनकी दोबारा पुष्टि की जाती है और इसके बाद जन्म और मृत्यु की गणना की जाती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानः

- भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक महीने की 9वीं तारीख को निश्चित रूप से व्यापक और गुणवत्तापूर्व प्रसव-देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में चिकित्सकों द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिये निजी क्षेत्र के डॉक्टरों के समर्थन के साथ-साथ जन्मपूर्व देखभाल सेवाओं का एक न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत प्रत्येक माह की निश्चित नवीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है।
- इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि (गर्भावस्था के 4 महीने के बाद) के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) देश में तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।

स्रोतः टाइम्स ऑफ इंडिया

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राजव्यवस्था, एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून 2018 को पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।

☞ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

☞ इस संस्था में सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी है।

मुख्य तथ्य :

❑ एनईसी राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है. नई व्यवस्था के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे तथा पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे।

❑ यह परिषद अंतर-राज्य विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।

❑ एनईसी के नए स्वरूप से यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कारगर संस्था बनेगी।

❑ एनईसी अब मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा विवादों जैसे अंतर-राज्य विषयों पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए जा रहे कार्यों को करेगी।

❑ परिषद समय-समय पर परियोजना में शामिल परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, इन परियोजनाओं आदि के लिए राज्यों के बीच समन्वय के लिए कारगर उपायों की सिफारिश करेगी। परिषद को केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियां प्राप्त होंगीं।

पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) :

❑ पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी एक बुनियादी संस्था है।

❑ एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी. इसकी स्थापना संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- वर्ष 2002 के संशोधन के बाद एनईसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और एनईसी इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बनाते समय दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। परिषद सिक्किम के मामले में विशेष परियोजनाएं और योजनाएं बनाएगी।
- एनईसी ने पूर्वोत्तर विजन 2020 को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके अंतर्गत लक्ष्य, इनकी रूपरेखा, चुनौतियों की पहचान और विभिन्न क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और विकास के लिए क्रियान्वयन रणनीति बनाई गई है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत विकास की रूपरेखा बनाने में मदद मिली है।

स्रोत: पीआईबी

'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' का गठन

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्र सरकार ने 01 जून 2018 कावेरी जल बंटवारे विवाद के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया है।

मुख्य तथ्य:

- यह प्राधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल के बंटवारे पर विवाद का समाधान करेगा।
- उच्चतम न्यायालय ने 16 फरवरी 2018 को केंद्र सरकार को आदेश के छह सप्ताह के भीतर प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया था।
- इस आदेश में कावेरी के जल में कर्नाटक के हिस्से में मामूली वृद्धि की गई थी, जबकि तमिलनाडु के लिए आवंटन कम कर दिया गया था। इसके साथ ही दक्षिण के दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा विवाद का समाधान करने की मांग की गई थी।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का संरचना और शक्तियां:

- प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, आठ सदस्य और एक सचिव होंगे। इनमें दो-दो पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे। बाकी चार अंशकालिक सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
- यह प्राधिकरण और इसके तहत बनाई गई कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ही नदी के पानी के बंटवारे के मसले पर विवाद का निपटारा करेगी। साथ ही इस बाबत उच्चतम न्यायालय और कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के आदेश लागू करेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कावेरी जल विवाद:

- कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का मसला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच लंबे समय से उलझा हुआ है। कावेरी एक अंतरराज्यीय नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं। इस घाटी का एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है और समुद्र में मिलने से पहले ये नदी कराइकाल से होकर गुजरती है, जो पुडुचेरी का हिस्सा है। इसलिए इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर इन चारों राज्यों में विवाद चल रहा है।
- कावेरी नदी के बँटवारे को लेकर चल रहा विवाद 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उस वक्त ब्रिटिश राज के तहत ये विवाद मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज के बीच था। वर्ष 1924 में इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। लेकिन बाद में इस विवाद में केरल और पुडुचेरी भी शामिल हो गया और यह विवाद और जटिल हो गया।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 01 जून 2018 को मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है।

  केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मई 2018 को इम्फाल में पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी थी।

मुख्य तथ्य:

- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश , 2018 राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 की तर्ज पर होगा जिसे 10 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल प्रशिक्षण समेत खेल शिक्षा को बढ़ावा देगा।
- विधेयक में इस बात का जिक्र है कि विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अपने तरह का इकलौता होगा और यहां अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के खेल प्रदर्शन में भी सुधार करेगा। इससे रोजगार उत्पादन भी बढ़ेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि:

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट भाषण में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव की घोषणा की थीं।
- विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, मणिपुर सरकार ने लगभग 325.90 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है।
- विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है और इसके लिए 524 करोड़ रुपये बजट की मंजूरी भी मिल गई है।
- फिलहाल देश में कुछ संस्थान हैं जो एथलीट और कोच के लिए विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम चलाते हैं लेकिन खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन वाले प्रशिक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश के खेल वातावरण में कमी है। इस खेल विश्वविद्यालय से यह कमी पूरी हो जाएगी।

स्रोत: पीआईबी

यूजीसी को समाप्त करके नया आयोग बनाने हेतु प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के स्थान पर भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए एक मसौदा बिल तैयार किया है।
- मसौदा बिल के अनुसार भारत का नया उच्च शिक्षा आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जबकि वित्तीय अधिकार मंत्रालय के अधीन होंगे। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े बदलाव करने जा रही है। मानसून सत्र में सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है।
- यह योजना लंबे समय से विचाराधीन थी। नया नियामक बनाने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 7 जुलाई 2018 को ड्राफ्ट बिल के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव के लिए सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और जनता से अपील की गई है।

मुख्य तथ्य:

- मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री और नीती आयोग नये कानून पर काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें नीति आयोग के सीईओ और हाईयर एजूकेशन सचिव सहित अन्य सदस्य इसके ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं।
- नया नियामक (सिंगल रेगुलेटर) के आने के बाद क्षेत्राधिकार में ओवरलैपिंग नहीं होगी. वहीं उन नियामक प्रावधानों को भी खत्म कर देगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यूजीसी और एआईसीटीसी को हटाकर एक सिंगल रेग्यूलेटर का आना सबसे क्लीन और बड़ा रिफॉर्म होगा। यूजीसी को खत्म करने के लिए यूपीए सरकार के समय गठित यशपाल समिति, हरी गौतम समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन इसको कभी अमल में नहीं लाया गया।
- मसौदे बिल में दावा किया है कि नया संस्थान कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा और शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाएगा और छात्रों को अधिक किफायती लागत पर अधिक अवसर प्रदान करेगा।

फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार:

- पहली बार, नियामक के पास अकादमिक गुणवत्ता मानकों को लागू करने की शक्तियां होंगी। उसे फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार भी होगा। मसौदा बिल के अनुसार अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
- वर्तमान में, यूजीसी जनता को सूचित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर फर्जी संस्थानों के नाम जारी करता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):

- भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है।
- यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यूजीसी का छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में हैं।
- यह राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) का भी आयोजन करता है जिसे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'जेलों में महिलाएं' विषय पर रिपोर्ट जारी की

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'जेलों में महिलाएं' विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट में राष्ट्रीय आदर्श जेल मैन्युअल 2016 में विभिन्न परिवर्तन का सुझाव दिया गया है ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

मुख्य तथ्य

- इस रिपोर्ट में 134 सिफारिशें की गई हैं, ताकि जेल में बंद महिलाओं के जीवन में सुधार लाया जा सके. गर्भधारण तथा जेल में बच्चे का जन्म, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, समाज के साथ एकीकरण और उनकी सेवाभाव जिम्मेदारियों पर विचार के लिए ये सिफारिशें की गई हैं।
- इस विषय का मुख्य उद्देश्य महिला बंदियों के विभिन्न अधिकारों के बारे में समझदारी कायम करना, उनकी समस्याओं पर विचार करना और उनका संभव समाधान करना है।

- मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी करते हुए बताया कि वर्ष 2015 के डेटा के अनुसार, भारतीय जेलों में 4,19,623 कैदी बंद हैं, जिसमें 17,834 यानी लगभग 4.3 फीसद महिलाएं हैं. इनमें से करीब 11,916 महिला विचाराधीन कैदी हैं।
- भारतीय जेलों के पांच सालों में किए जाने वाले विश्लेषण में कहा गया है कि महिला कैदियों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है।
- वर्ष 2000 में जहां महज 3.3 फीसदी थीं वह वर्ष 2015 में 4.3 फीसदी हो गई हैं. ज्यादातर महिला कैदियों की उम्र 30–50 के बीच है।

'जेलों में महिलाएं' विषय पर रिपोर्ट:

- रिपोर्ट में महिला बंदियों की अनेक समस्याओं को कवर किया गया है और इसमें बुजुर्गों तथा दिव्यांग लोगों की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में न केवल गर्भवती महिलाओं की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। बल्कि उन महिलाओं पर भी विचार किया गया है जिन्होंने हाल में बच्चे को जन्म दिया गया है लेकिन उनके बच्चे जेल में उनके साथ नहीं हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल में बंद करने से पहले सेवा देखभाल जिम्मेदारी वाली महिलाओं को अपने बच्चों को प्रबंध करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- रिपोर्ट में उन विचाराधीन महिला कैदियों को जमानत देने की सिफारिश की गई है जिन्होंने अधिकतम सजा का एक तिहाई समय जेल में बिताया है। ऐसा कानूनी प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 436 ए में आवश्यक परिवर्तन करके किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी करने पर रिहाई का प्रावधान है।
- जेलों में शिकायत समाधान व्यवस्था अपर्याप्त है और इस व्यवस्था में दुरूपयोग और बदले की भावना से काम करने की गुंजाइश बनी हुई है।
- बंदियों की मानसिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि कम से कम साप्ताहिक आधार पर बंदियों का संपर्क महिला काउंसिलरों और महिला मनोवैज्ञानिकों से हो सके।
- जेल में बंद महिलाओं को अपने पुरूष बंदियों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी बंदी से उन पर सामाजिक धब्बा लगता है क्योंकि महिला बंदी वित्तीय रूप से अपने परिवारों और पतियों पर निर्भर करती हैं।
- प्रसव पश्चात के चरणों में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए रिपोर्ट में माताओं के लिए बच्चा जन्म देने के बाद पृथक आवासीय व्यवस्था की सिफारिश की गई है, ताकि साफ–सफाई का ध्यान रखा जा सके और नवजात शिशु को संक्रमण से बचाया जा सके।
- कानूनी सहायता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी विचार–विमर्श गोपनीयता के साथ और बिना सेंसर के किया जाना चाहिए।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- समाज में महिलाओं का फिर से एकीकरण गंभीर समस्या है क्योंकि जेल में बंद होने से महिलाओं पर धब्बा लगता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि जेल में बंद महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया है।
- रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि जेल अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करें कि महिला बंदी रिहाई के बाद प्रताड़ित न हों। बंदी महिलाओं को मताधिकार देने की सिफारिश की गई है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान टेक-थॉन के आयोजन की घोषणा

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में पोषण अभियान के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारी 'टेक-थॉन' पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित करने की घोषणा की।

पोषण अभियान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है।

पोषण अभियान टेक-थॉनः

- इस सेमिनार का आयोजन पोषण अभियान को दिखाने और इस संबंध में वातावरण बनाने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा प्रौद्योगिकी समर्थन के लिए सहयोग और साझेदारी की संभावना तलाशने तथा पोषण की दिशा में जन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए लाभार्थियों में कारगर व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है।
- यह अभियान अगले कुछ वर्षों में विभिन्न मानकों पर हासिल किए जाने वाले विशेष लक्ष्यों पर बल देता है। इससे पहले देश में शीर्ष स्तर पर पोषण को इतना महत्व नहीं दिया था।
- पोषण अभियान में कारगर निगरानी और समय पर कार्रवाई के माध्यम से विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और सॉफ्टवेयर सेवा डिलीवरी को मजबूत बनाने तथा पोषण परिणामों को सुधारने में मदद करेगा।
- सेमिनार में भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के नीति निर्माता, यूनिसेफ, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएफपी जैसे बहुपक्षीय सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधि, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोगी-टाटा ट्रस्ट, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), परोपकारी निजी क्षेत्र तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे और प्रौद्योगिकी समर्थन के लिए सहयोग और साझेदारी पर प्रकाश डालेंगे.
- प्रवासी भारतीय केंद्र की गैलरी में टेक्नॉलोजी तथा पोषण अभियान पर प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- सेमिनार में लगभग 300 लोग भाग लेंगे।

कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस):

- कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस) विशेष रूप से विकसित किया गया है जो डाटा ग्रहण करने का कार्य सक्षम करता है।
- पोषण अभियान अग्रणी कर्मियों यानी आंगनवाड़ी कर्मी तथा महिला निरीक्षक को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराकर सशक्त बनाता है।
- निर्धारित सेवा डिलीवरी सुनिश्चित करता है और जहां कही आवश्यक हो कार्रवाई के लिए तत्पर बनाता है।
- यह फिर सेक्टर, ब्लॉक, जिला, राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक डैशबोर्ड के माध्यम से निरीक्षणकर्मियों को वास्तविक समय में निगरानी के लिए डाटा उपलब्ध कराता है।
- वर्ष 2020 तक इस एप्लीकेशन को 14 लाख आंगनवाड़ियों में लागू किया जाएगा और करीब 10 करोड़ लाभार्थियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
- अब यह विश्व में सबसे बड़ा ई-पोषण तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम है. जिसमें 7 राज्यों (मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में कर्मियों के साथ 1.1 लाख डाटा एंट्री उपकरण है जिससे 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिलेगी।

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) :

- पोषण अभियान, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुंनू में शुभारंभ किया गया था।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन करेगा।
- यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा।
- इससे बेहतर निगरानी समय पर कार्यवाही के लिए सावधानी जारी करने में तालमेल बिठाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्य करने, मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- मिशन का लक्ष्य बच्चों में उनकी लम्बाई कम बढ़ने की समस्या (स्टंटिंग) का निवारण करना भी है।
- इस मिशन का मुख्य लक्ष्य कुपोषण और जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने संबंधी समस्याओं को प्रत्येक वर्ष 2% तक कम करना है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारत में 38.4% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं।
- मिशन का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक इसमें कमी लाते हुए इसे 25% तक लाया जाए।
- मिशन का लक्ष्य एनीमिया से पीड़ित बच्चों, महिलाओं तथा किशोरों की संख्या में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाना है।
- यह मिशन वर्ष 2017-18 के दौरान 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष जिले कवर किये जाएंगे।
- इस मिशन में आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) जैसे कई घटक शामिल होंगे, जो रियल-टाइम निगरानी प्रणाली पर आधारित होंगे।

वर्तमान में, अभियान के अंतर्गत 550 जिले कवर किए गए हैं, समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए 2020 तक चरणबद्ध तरीके से सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा 718 जिलों को कवर किया जाएगा।

स्रोतः पीआईबी

&&&&

ELITE IAS

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018: भारत 137 वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

☞ इंस्टिट्यूट फॉर इकनॉमिक्स ऐंड पीस (आईईपी) द्वारा जारी किए गए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में भारत 163 देशों की सूची में 137 वें स्थान पर रहा।

☞ भारत वर्ष 2017 में इस सूची में 141वें स्थान पर था और इस बार भारत की रैंकिंग में चार स्थान की बढ़ोतरी का कारण हिंसक अपराध के स्तर में कमी को बताया जा रहा है।

मुख्य तथ्य:

❑ इस सूची के मुताबिक विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है, शांतिपूर्णता के मामले मंथ आइसलैंड की यह सर्वोच्च स्थिति वर्ष 2008 से ही बनी हुई है।

❑ आइसलैंड के बाद इस सूची के शीर्ष पांच देशों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और डेनमार्क आते है।

❑ साथ ही दूसरी तरफ विश्व का सबसे अशांत देश सीरिया है। वह इस स्थान पर पिछले पांच वर्षो से कायम है।

❑ अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, इराक और सोमालिया सूची में सबसे नीचे आने वाले अर्थात सबसे कम शांतिपूर्ण देश हैं।

❑ मौतों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी वाले देशों में श्रीलंका, चाड, कोलंबिया और युगांडा के साथ-साथ भारत भी मुख्य देश रहा है।

❑ वर्ष 2017 की तुलना में श्रीलंका सूची में 80 से 67 वें स्थान पर, नेपाल 93 से 84 वें स्थान पर, पाकिस्तान 152 से 151 वें स्थान पर जबकि भूटान 13 से 19 वें स्थान पर और बांग्लादेश 84 से 93 वें स्थान पर आ गया है।

❑ शांति में सबसे ज्यादा कमी दक्षिण अमेरिका में आई है. आतंकवाद की बढती घटनाएँ और जेल में बंदी की बढ़ती दर की वजह से ऐसा हो रहा है।

पृष्ठभूमि:

☞ रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक शांति का स्तर पिछले साल के मुकाबले 0.2 फीसदी घट गया है. यह लगातार चौथा साल है जब शांति का स्तर पहले से घटा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वैश्विक नेतृत्व अशांति का कारण बने मसलों को हल करने की दिशा में कोई कारगर पहल नहीं कर पाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दशक में उभरे मसले भी अब तक सुलझाए नहीं जा सके हैं।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

जी 7 सम्मेलन: व्यापार में संरक्षणवाद के विरोध का संकल्प लिया गया

चर्चा में क्यों?

☞ अमेरिका सहित जी-7 समूह देशों के नेताओं की दो दिन की शिखर बैठक के बाद जारी साझा वक्तव्य में संक्षणवाद का मुकाबला करने और व्यापार की राह में बाधाएं कम करने का संकल्प व्यक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ, कनाडा और अन्य देशों से इस्पात तथा एल्युमीनियम के आयात पर ऊंचा आयात शुल्क लगाए जाने का निर्णय लिया है जबकि बाकी देश इसके पक्ष में नहीं थे। दरअसल, जी7 की बैठक में घोषणा हुई कि व्यापार की राह में आने वाली बाधाओं को कम किया जाएगा। इसका इशारा अमेरिका की ओर से विदेशी सामान पर लगाए जाने वाले टैक्स से था।

जी-7 घटनाक्रम

- ❑ जी-7 सम्मेलन सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियों का सम्मेलन है जिसमें हुए घटनाक्रम ने विश्व को स्तब्ध किया है।
- ❑ सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तय समय से पहले ही सम्मलेन छोड़ने का निर्णय किया।
- ❑ बैठक में यह घोषणा की गई कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम किया जायेगा।

जी-7 सम्मेलन के बारे में

☞ जी-7 शिखर सम्मेलन मूल रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान का गुट है। यह उन समस्याओं और संकटों पर विचार करने के लिए वर्ष में एक बार शिखर बैठक करता है जिनका इन देशों की नजर में अधिक अंतरराष्ट्रीय महत्व है। सम्मेलन के निर्णय न तो किसी संधि-समझौते जैसे बाध्यकारी होते हैं और न ही वैसा कोई औपचारिक महत्व रखते हैं। प्रत्येक शिखर सम्मेलन इन देशों के प्रमुखों के स्तर पर ऐसे अनौपचारिक विचार-विमर्श का काम करता है, जो विभिन्न मुद्दों पर एक जैसी नीति अपनाने या किन्हीं भावी संधियों-समझौतों पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर सके।

स्रोत: द हिंदू

अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद छोड़ने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

☞ अमेरिका ने 19 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने की घोषणा की. अमेरिका लंबे समय से मानवाधिकार परिषद में सुधार किये जाने की मांग करता रहा है तथा मांग न मानने पर बाहर होने की चेतावनी देता रहा है।

☞ अमेरिका का आरोप है कि 47 सदस्यों वाली यह परिषद इजराइल विरोधी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिका की दूत निकी हेली ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। निकी हैली ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने की घोषणा करता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

घटनाक्रम

- अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के शासन काल में भी तीन साल तक मानवाधिकार परिषद का बहिष्कार किया था।
- इसके बाद ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद 2009 में वह इस परिषद में फिर से शामिल हुआ था।
- डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद सँभालते ही इस परिषद में सुधारों के लिए बात उठाई थी।
- अमेरिका तीन वर्ष के लिए इस परिषद का सदस्य बना था और अभी उसका डेढ़ वर्ष ही पूरा हुआ है।
- परिषद में सुधारों पर सहमति नहीं बनी और अमेरिका की मांगों को नहीं माना गया था।
- उसी के चलते अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हट जाने की घोषणा की गई।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु डील के बाद यह तीसरा अवसर है जब वह बहुपक्षीय समझौतों से अलग हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) का उद्देश्य विश्व में मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर नजर रखना है। वर्ष 2006 में इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। अमेरिका के अलावा अन्य 46 देश इसके सदस्य हैं। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद् ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया।
- इसका कार्य सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत निर्देशित होता है। इसे समय-समय पर सभी एजेंसियों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को व्यवस्थापरक ढंग से रोका जा सके।
- वर्तमान में भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2006-07, 2007-10, 2011-14 और 2013-17 में चार बार इसका सदस्य रह चुका है। वर्ष 2013 में चीन, रूस, सऊदी अरब, अल्जीरिया और वियतनाम को इसमें शामिल किए जाने पर मानवाधिकार समूहों ने इसकी आलोचना की थी।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मॉरीशस 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा

चर्चा में क्यों?

- 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरीशस सरकार के सहयोग से 18-20 अगस्त 2018 तक मॉरीशस में आयोजित किया जा रहा है। यह मॉरीशस सरकार के सहयोग से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय
- 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय 'वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कार' रहेगा।
- इसका स्थान स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, पाइल्स मॉरीशस होगा।

11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन :

- सम्मेलन स्थल पर हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कई प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी।
- इस सम्मेलन का लक्ष्य भाषा के योगदान के लिए विश्व के विभिन्न हिस्सों से कई हिंदी विद्वानों, लेखकों और विजेताओं को एक मंच प्रदान करना है।
- सम्मेलन के दौरान भारत एवं अन्य देशों के हिंदी विद्वानों को हिंदी के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए विश्व हिंदी सम्मान" से सम्मानित किया जाएगा।
- सम्मेलन में हिंदी के शास्त्रीय और आधुनिक दोनों ही तत्व शामिल होंगे और विश्व भर से हिंदी के सहभागिता प्रतिनिधियों और विद्वानों को देखा जा सकेगा।
- पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था. तब से, विश्व के विभिन्न हिस्सों में दस ऐसे सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

विश्व हिन्दी सम्मेलन:

- विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिन्दी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिन्दी प्रेमी जुटते हैं।
- विश्व भर में हिंदी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हर तीन साल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- पहले सम्मेलन में, तत्कालीन मॉरीशस के प्रधानमंत्री सेवुसागुर रामगुलाम मुख्य अतिथि थे और इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' में शामिल किया

चर्चा में क्यों?

☞ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को एक बार फिर 'ग्रे लिस्ट' में बरकरार रखा है।

मुख्य तथ्य

- पाकिस्तान ने अपने वित्त मंत्री शमशाद अख्तर को देश के बचाव के लिए चुना है। अख्तर एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे और ग्रे सूची से नाम हटाने की मांग करेंगे। इसके साथ ही पाक वित्त मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एफएटीएफ को जानकारी देंगे।
- पाकिस्तान ने एफएटीएफ द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाले जाने से बचने के लिए 28 सूत्री योजना लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत उसने आईएस, अलकायदा, लश्कर ए ताइबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, जमात उद दावा (जेयूडी) एवं इसकी सहयोगी फलाह ए इंसानियत और तालिबान से संबद्धित व्यक्तियों को वित्तीय मदद रोकने का प्रस्ताव दिया है।
- इससे पहले पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे अख्तर ने अपने देश को ग्रे सूची से हटाने के लिए एफएटीएफ से आग्रह किया था लेकिन बावजूद इसके पेरिस में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकी समूहों को फंडिंग करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया।
- गौरतलब है कि आतंकवाद को आर्थिक मदद देने के चलते पाकिस्तान वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक एफएटीएफ के 'ग्रे लिस्ट' में शामिल रह चुका है।

इस कदम का महत्व

- ग्रे सूची पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है. इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हो सकता है।
- एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद किसी देश को इंटरनेशनल संस्थाओं द्वारा कर्ज मिलने में काफी परेशानी होती है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा।
- पाकिस्तान उद्योगपति भी अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए वैश्विक बाजार से पूंजी नहीं उठा पाएंगे।
- पेरिस में हुई अंतर-सरकारी निकाय एफएटीएफ की बैठक में शामिल 37 देशों में से 36 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। जबकि एकमात्र तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। पाकिस्तान को निगरानी सूची में डालने के प्रस्ताव को अमेरिका ने पेश किया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) :

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतर - सरकारी निकाय है जिसका गठन धनशोधन, आतंकवादियों के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को किसी तरह के अन्य खतरे से मुकाबले के लिए किया गया था।
- एफएटीएफ का गठन वर्ष 1989 में किया गया था।
- इसमें 37 स्थायी सदस्य हैं. इजरायल और सऊदी अरब पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं।
- यह धन को अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश भेजने, आतंकवाद को आर्थिक मदद देने और वैश्विक आर्थिक ढांचे के लिए अन्य खतरनाक तरीकों पर नजर रखता है।
- संगठन द्वारा लिया गया फैसला सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होता है।

स्रोतः द हिंदू

नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- इस समझौता ज्ञापन का शीर्षक नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच अभिरूचि की संयुक्त घोषणा है। संयुक्त घोषणा से भारत और जर्मनी के बीच विमान परिवहन में कारगर विकास होगा।

मुख्य तथ्य :

- इस समझौता ज्ञापन से भारत और जर्मनी के बीच नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया जा सकेगा जिससे व्यापार, निवेश, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- दोनों देशों ने नागर विमानन क्षेत्र में ज्ञानतथा अनुभव को साझा करने के लिए अभिरूचि की संयुक्त घोषणा के माध्यम से संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकसित करने की इच्छा व्यक्त की।

संयुक्त घोषणा का मुख्य उद्देश्य

- ***विमानन सुरक्षा तथा एयर ट्रैफिक प्रबंधन :*** सेमीनारों, गोष्ठियों, एक दूसरे देशों की यात्राओं तथा अन्य विचारों सहित विमान सुरक्षा गतिविधियों तथा सुरक्षा निगरानी से संबंधित सूचना और श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करना।
- ***हेलीपोर्ट तथा हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवा (एचईएमएस) :*** हेलीपोर्ट तथा हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवाओं से संबंधित सूचना तथा श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करना है।
- ***प्रशिक्षण और कौशल विकास :*** तकनीकी तथा गैर-तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण विशेषकर विमानन सुरक्षा निगरानी में साझेदारी की संभावना तलाशना है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- ***नियमन तथा नीति :*** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आईसीएओ में सहयोग जारी रखना।
- **कॉरपोरेट तथा व्यवसाय विमानन विकास :** व्यवसाय तथा गैर-वाणिज्यिक विमानन के लिए सुविधाओं पर सूचना साझा करना है।
- **पर्यावरण :** सतत तथा पर्यावरण अनुकूल एयरोड्रोम विकास तथा नियोजन पर फोकस के साथ एयरोड्रमों की सरकारी निगरानी से संबंधित अनुभव को साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना तथा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संबंधित ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों का समाधान करना है।

स्रोत: पीआईबी

SIPRI रिपोर्ट: केवल दो देशों के पास विश्व के 92% परमाणु हथियार

चर्चा में क्यों?

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा परमाणु हथियारों से जुड़ी रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल दो देशों के पास दुनियाभर के 92 प्रतिशत परमाणु हथियार मौजूद हैं।
- रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान और चीन के परमाणु हथियारों की संख्याओं का भी विवरण दिया गया है। सीपरी (SIPRI) की इस रिपोर्ट के अनुसार अभी विश्व में लगभग 14,650 परमाणु शस्त्र मौजूद हैं।

SIPRI रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रूस के पास 6850 और अमेरिका के पास करीब 6450 परमाणु शस्त्र मौजूद हैं जो कि विश्व में सबसे अधिक हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 140-150 है जबकि भारत के पास 130-140 परमाणु हथियार हैं।
- सीपरी के अनुसार चीन के पास भारत और पाकिस्तान दोनों से अधिक 280 परमाणु हथियार हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के पास लगभग 80, फ्रांस के पास 300 और ब्रिटेन के पास लगभग 215 परमाणु हथियार हैं।
- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया के पास इस साल की शुरुआत में 14 हजार 465 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,750 को तैनात किया जा चुका है।
- रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 14465 परमाणु हथियार हैं। जबकि 2017 में इनकी संख्या 14935 थी।
- रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की परमाणु शक्तियां अब इन हथियारों को धीरे-धीरे कम कर रही हैं लेकिन चिंता की बात ये शक्तियां परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण भी कर रही हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विभिन्न देशों में परमाणु हथियारों की स्थिति

देश	परमाणु हथियार
रूस	6850
अमेरिका	6450
फ्रांस	300
ब्रिटेन	215
चीन	280
पाकिस्तान	140–150
भारत	130–140
इजरायल	80
उत्तर कोरिया	10–20

☞ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार भंडार का विस्तार कर रहे हैं और नए जमीन, समुद्र और वायु में मार करने वाले मिसाइल डिलिवरी सिस्टम का विकास कर रहे हैं। चीन भी अपने परमाणु हथियार प्रणाली का विकास कर रहा है और धीरे-धीरे अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। चीन लगातार अपने परमाणु हथियार प्रणाली का आधुनीकिकरण कर रहा है और अपने हथियारों के आकार को छोटा बना रहा है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

'सौर चरखा मिशन'

चर्चा में क्यों?

☞ राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर 'सौर चरखा मिशन' शुरू किया, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके।

सौर चरखा मिशन के बारे में :

- सौर चरखा मिशन में 50 समूह शामिल होंग।
- यह मिशन कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं।
- यह मिशन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्त करेगा।
- इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदिन कर दिया गया है।
- इस मिशन के लिए एमएसएमई मंत्रालय कारीगारों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगा।
- सौर चरखा मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा, जो पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।
- सौर चरखा मिशन का मुख्य लक्ष्य देश भर में पांच करोड़ महिलाओं को जोड़ना है.
- इस योजना के तहत, सरकार पहले दो वर्षों के दौरान एक लाख महिलाओं को नौकरियां देगी।
- सौर चरखा मिशन 2018 के तहत महिलाओं के लिए एक नया काम पाने का एक शानदार अवसर होगा।
- इस योजना को विशेष रूप से देश भर में महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया हैं।

संपर्क पोर्टल :

- राष्ट्रपति ने एमएसएमई मंत्रालय का 'संपर्क' नामक एक पोर्टल भी शुरू किया।
- यह पोर्टल प्रतिभाशाली उद्यमियों और प्रशिक्षित लोगों की तलाश कर रहे उद्यमों के बीच सेतू का कार्य करेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) :

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
- भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45% हिस्सा है। केन्द्रीय या राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- एमएसएमई क्षेत्र उद्यमशीलता के लिए प्रजनन भूमि की तरह होता है, जोकि अक्सर वैयक्तिक सृजनशीलता और नवाचार से संचालित होता है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8 फीसदी, विनिर्मित उत्पादन में 45 और इसके निर्यात में 40 फीसदी का योगदान देता है।
- एमएसएमई क्षेत्र में वृहत उद्यमों की तुलना में रोजगार क्षमता और सकल वृद्धि बहुत ज्यादा होती है।

स्रोतः पीआईबी

'सूर्य शक्ति योजना'

चर्चा में क्यों?

- गुजरात सरकार ने किसानों की बिजली समस्या के समाधान हेतु 'सूर्य शक्ति किसान योजना' शुरू की है. गुजरात के 18 हजार गांवों को बिजली पहुंचाने वाली ज्योति ग्राम योजना के बाद राज्य सरकार ने किसानों की बिजली समस्या के स्थायी समाधान हेतु यह योजना शुरू की है।
- इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- सरकार किसानों को खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए एक बड़ी राशि की सब्सिडी भी देगी। योजना के द्वारा सरकार को प्रति वर्ष 175 मेगावाट बिजली प्राप्त होने की आशा है।
- इस योजना के द्वारा मिलने वाली बिजली को किसान अपने कार्यों में उपयोग करेंगे और साथ ही बची बिजली सरकार को बेच भी सकते है जिसका मुनाफा किसान ही रखेंगे।

योजना से संबंधित मुख्य तथ्य :

- गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने किसानों की बिजली समस्या के स्थायी समाधान हेतु 870 करोड़ रुपये की लागत से सूर्यशक्ति किसान योजना शुरू की है। किसानों को नाबार्ड की ओर से कर्ज दिया जाएगा।
- इस नई योजना के लिए किसानों को सौर परियोजना की स्थापना के कुल व्यय का केवल 5 प्रतिशत ही खर्च करना होगा।
- केंद्रीय और राज्य सरकारें परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी जबकि 35 प्रतिशत हिस्सा किसानों द्वारा सात साल की अवधि में भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत किसानों को कम वोल्टेज की समस्या के बिना दिन में 12 घंटे बिजली मिलेगी.
- यह योजना उन किसानों हेतु है, जो बिजली कंपनियों के मौजूदा उपभोक्ता हैं. इस योजना के तहत पानी और बिजली की बचत होगी। साथ ही किसान की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आरबीआई ने बॉन्ड में विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत बड़े निगमों में निवेश मानदंडों को आसान बना दिया है।

केंद्रीय बैंक के इस कदम से बॉन्ड में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता :

- एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में निवेश करने की अनुमति है, जिसमें ट्रेजरी बिल और एसडीएल शामिल हैं, बिना किसी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता के, इस शर्त के अधीन कि किसी भी श्रेणी के तहत एफपीआई द्वारा अल्पकालिक निवेश 20 से अधिक नहीं होगा।
- केंद्रीय बैंक ने एफपीआई को मैच्योरिटी में कम से कम एक साल शेष अवधि वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश की इजाजत दी है।
- एफपीआई द्वारा कॉरपोरेट बॉन्ड में अल्पावधि निवेश कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई के कुल निवेश का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- एफपीआई द्वारा अल्पावधि निवेश कुल निवेश का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की आवश्यकता अंत-दर-दिन आधार पर लागू होती है।

एफपीआई द्वारा निवेश :

- एफपीआई द्वारा निवेश, जिसमें संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश शामिल है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के किसी भी मुद्दे के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि संबंधित एफपीआई समेत एक एफपीआई ने किसी भी मुद्दे के 50 प्रतिशत से अधिक में निवेश किया है, इस शर्त को पूरा होने तक यह उस मुद्दे में और निवेश नहीं करेगा।
- कोई एफपीआई अपने कॉरपोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो का 20 प्रतिशत से अधिक एक कॉर्पोरेट (कॉर्पोरेट से संबंधित संस्थाओं के संपर्क में) के संपर्क में नहीं होगा।
- एफपीआई को मैच्योरिटी में कम से कम 3 साल शेष अवधि वाले सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की इजाजत दी गई थी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) :

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को कई तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की इजाजत है। इनमें सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन और कॉर्पोरेट बॉन्ड शामिल हैं। इनमें निवेश के लिए विदेशी निवेशकों के वास्ते कुछ सीमाएं और शर्तें भी तय की गई हैं।
- एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति थी जब तक कि सीमा उपयोग 90 प्रतिशत तक पहुंच न जाए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश वित्तीय संपत्तियों के प्रत्यक्ष स्वामित्व के साथ निवेशक प्रदान नहीं करता है।

स्रोतः द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड

आरबीआई ने 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' आयोजित किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' शुरू किया है। यह वित्तीय साक्षरता सप्ताह 04 जून से 08 जून 2018 तक आयोजित किया जाएगा।

  'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' का थीम और उद्देश्य

  'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' का थीम ग्राहकों का संरक्षण (Customer Protection) रखा गया है।
- वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को डिजीटल बैंकिंग के प्रति जागरूक करने के अलावा सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली अपनाने बारे जागरूक करना है।

मुख्य तथ्य :

- सप्ताह के दौरान बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर ग्राहकों को चार विषयों के बारे में जानकारी दी जायेगी। इसमें फर्जी निवेश योजनाओं के झाँसे में न आने, बैंकिंग संबंधी शिकायत के लिए 'बैंकिंग लोकपाल' व्यवस्था के प्रयोग, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के लिए क्या करें, क्या न करें और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक तथा बैंकों की देयता के बारे में बताया जायेगा।
- वित्तीय रूप से पिछड़े एवं वंचित इलाकों में सभी बैंकों की शाखाओं में कार्यशालाओं, शिविरों, प्रश्नोत्तरी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये गये हैं।
- आरबीआई ने डिजिटल माध्यम से लेनदेन बढ़ने के साथ ही ग्राहकों को इसमें होने वाली धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया है।
- आरबीआई ने कहा है कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी होने पर ग्राहक को तीन दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिये, उसके बाद पूरी जवाबदेही बैंक की होगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- आरबीआई के अनुसार ग्राहकों को एटीएम से असफल लेन-देन, ग्राहक की जानकारी के बिना बैंक खाते में शुल्क लगना आदि के बारे में ग्राहक अपनी शाखा में शिकायत कर सकते हैं। एक महीने के अंदर समाधान नहीं होता है तो बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत कर सकते हैं।
- वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अन्य फोकस बिंदुओं में आरबीआई की बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। इस कार्यक्रम में बैंकर, वित्तीय साक्षरता सलाहकार और अन्य वित्तधारक प्रमुख प्रतिभागी होंगे।

बैंकिंग लोकपाल योजना

- बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिये आरम्भ की गयी एक योजना है।
- इसके अन्तर्गत एक 'बैंकिंग लोकपाल' की नियुक्ति की जाती है जो एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी है। वैसे तो बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में लागू की गई थी, लेकिन वर्ष 2002 एवं वर्ष 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए संशोधन किए गए, ताकि बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभाव रहित और जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखती है।
- ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत और समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत डाक, ई मेल, आन लाइन दर्ज करा सकता है। इस शिकायत का निस्तारण तीस दिन के अंदर किया जाता है।
- ग्राहकों की सुविधा व बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए यह योजना संचालित है।

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

केंद्र सरकार ने 'कृषि कल्याण अभियान' आरंभ किया

चर्चा में क्यों?

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि कल्याण अभियान की शुरूआत की है. इसके तहत किसानों को उत्तम तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी।
- कृषि कल्याण अभियान का आयोजन नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 01 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 के बीच किया जा रहा है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

- कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन, कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग मिलकर जिलों के 25-25 गांवों में कार्यक्रमों का संचालन करेंगे।
- प्रत्येक जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र सभी 25-25 गांवों में कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग करेंगे।
- प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को कार्यक्रम की निगरानी करने एवं सहयोग करने का प्रभार दिया गया है. इन अधिकारियों का चयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों से किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

गतिविधियां

- मृदा स्वास्थ्य कार्डों का सभी किसानों में वितरण
- प्रत्येक गांव में जानवरों के खुर और मुंह रोग (एफएमडी) से बचाव के लिए सौ प्रतिशत बोवाइन टीकाकरण।
- भेड़ और बकरियों में बीमारी से बचाव के लिए सौ फीसदी कवरेज।
- सभी किसानों के बीच दालों और तिलहन की मिनी किट का वितरण।
- प्रति परिवार पांच बागवानी/कृषि वानिकी/बांस के पौधों का वितरण।
- प्रत्येक गांव में 100 एनएडीएपी पिट बनाना।
- कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना।
- सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन।
- बहु-फसली कृषि के तौर-तरीकों का प्रदर्शन।

कृषि कल्याण अभियान की विशेषताएं

- कृषि कल्याण अभियान आकांक्षी जिलों के 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक 25 गांवों में चलाया जा रहा है।
- इन गांवों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- जिन जिलों में गांवों की संख्या 25 से कम है, वहां के सभी गांवों को (1000 से अधिक आबादी वाले) इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है।

स्रोतः पी टी आई

द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति, 2018-19

चर्चा में क्यों?

- 6 जून, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य-2018-19 (Second Bi&monthly Monetary Policy Statement) जारी किया।

मुख्य तथ्यः

- आरबीआई ने द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF% Liquidity Adjustment Facility) के अंतर्गत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया है।
- परिणामतः चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 6.0 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर (Marginal Standing Facility Rate) और बैंक दर 6.50 प्रतिशत है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR% Statutary Liquidity Ratio) को अपरिवर्तित रखते हुए 19.50 प्रतिशत पर रखा गया है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात (CRR% Cash Reserve Ratio) को अपरिवर्तित रखते हुए इसे निवल मांग और मियादी देयताओं (NDTL% Net Demand and Time Liabilities) के 4 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वास्थ्य

केंद्र सरकार ने 'गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक' स्थापित करने को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

☞ केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 'गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक' स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा तीन अन्य पदक-आंतरिक सुरक्षा पदक, असाधारण आसूचन पदक तथा उत्कृष्ट एवं अति-उत्कृष्ट सेवा पदक भी प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

मुख्य तथ्य :

- असाधारण साहस का परिचय देने वाले पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलकर्मियों को अब 'गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक' तथा तीन अन्य पदकों से भी सम्मानित किया जाएगा।
- गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारी, केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा विशेष अभियान में शामिल सुरक्षा संगठन के अधिकारी पात्र होंगे।
- ये सभी पदक हर साल प्रदान किए जाएंगे। गृह मंत्री का विशेष संचालन पदक तथा असाधारण आसूचन पदक स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर प्रदान किया जाएगा जबकि आंतरिक सुरक्षा पदक तथा उत्कृष्ट एवं अति-उत्कृष्ट सेवा पदक गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर घोषित किया जाएगा।
- असाधारण आसूचन पदक केन्द्र सरकार के गुप्तचर संगठन के अधिकारियों, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के गुप्तचर अधिकारियों, सीपीओ, सीएपीएफ, असम राइफल्स (एआर) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के अधिकारियों को उनके असाधारण उत्साह और गुप्तचर सूचनाएं प्राप्त करने में कुशलता के लिए दिया जाएगा।
- इसी तरह से आंतरिक सुरक्षा पदक राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों, सीपीओ, सीएपीएफ, सुरक्षा संगठन कर्मियों को जम्मू-कश्मीर, माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत पुलिसकर्मियों को हर दो साल के कार्यकाल के आधार पर दिया जाएगा।
- उत्कृष्ट तथा अति-उत्कृष्ट सेवा पदक सीएपीएफ, राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के पुलिस बलों, सीपीओ, एआर,एनएसजी, होम गार्ड तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और सीएपीएफ के स्थायी पुलिस कर्मियों को 15 और 25 वर्षों की सेवा के आधार पर दिया जाएगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कोई सीमा/कोटा नहीं :

☞ गृह मंत्री का विशेष संचालन पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक और असाधारण आसूचन पदक देने के लिए कोई सीमा/कोटा नहीं होगा. लेकिन क्रमशः उत्कृष्ट तथा अति-उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए पात्रता शर्तों के साथ रैंक के अनुसार (कांस्टेबल/एचसी/एएसआई/ एसआई /इंस्पेक्टर/ डिप्टी एसपी/एसपी और उससे ऊपर) स्वीकृत संख्या बल के एक प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत की सीमा होगी।

☞ निष्ठाहीनता का दोषी पाए जाने या बल के सम्मान को ठेस पहुंचाने पर धारक से पदक वापस ले लिया जाएगा।

स्रोतः द हिंदू

भारत ने 'अग्नि-5' मिसाइल का सफल परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

☞ भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और स्वदेश में विकसित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का 03 जून 2018 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

मुख्य तथ्य

❑ इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के लांच पैड-4 से सचल प्रक्षेपक (मोबाइल लांचर) की मदद से प्रक्षेपित किया गया।

❑ यह अग्नि-5 का छठा परीक्षण था और यह पूरी तरह सफल रहा। इससे पहले 18 जनवरी 2018 को परीक्षण किया गया था।

❑ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अनुसार, अग्नि-5 श्रृंखला के अन्य मिसाइलों के विपरीत, अग्नि-5 नेविगेशन और गाइडेंस, वॉरहैड और इंजन के संदर्भ में नई प्रौद्योगिकियों के साथ सबसे उन्नत है।

❑ अग्नि-5 मिसाइल का पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को किया गया था। दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को किया गया। तीसरा परीक्षण 31 जनवरी 2015 और चौथा परीक्षण 26 दिसंबर 2016 को किया गया। पांचवा परीक्षण 18 जनवरी 2018 को किया गया था। ये सभी परीक्षण भी सफल रहे थे।

'अग्नि-5' मिसाइल की खासियत

❑ यह मिसाइल बेहद शक्तिशाली है, और 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है।

❑ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल कई हथियार एक साथ ले जाने में सक्षम है।

❑ इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बनाया है।

❑ यह मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यह भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों में से एक है।
- इस मिसाइल की ऊंचाई 17 मीटर, जबकि व्यास 2 मीटर है।
- इसका वजन करीब 20 टन है.
- यह मिसाइल डेढ़ टन तक परमाणु हथियार ले जा सकती है।
- इसकी गति ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है।
- अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल बेहद आसान है। देश के किसी भी कोने में इसे तैनात कर सकते हैं जबकि किसी भी प्लेटफॉर्म से युद्ध के दौरान इसकी मदद ली जा सकती हैं।
- अग्नि 5 मिसाइल की कामयाबी से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि न सिर्फ इसकी मारक क्षमता 5 हजार किलोमीटर है, बल्कि ये परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है।
- अग्नि 5 मिसाइल से छोटे सैटेलाइट छोड़े जा सकेंगे। इससे दुश्मनों के सेटेलाइट को नष्ट करने में भी मदद मिलेगी।
- यह मिसाइल एक बार छूटी तो रोकी नहीं जा सकेगी। यह 1000 किलो का न्यूक्लियर हथियार ले जा सकेगी।
- अग्नि पांच के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि :

- अग्नि-5 मिसाइल के परीक्षण के दौरान स्वदेश निर्मित कई नयी प्रौद्योगिकियों का सफल परीक्षण हुआ. नौवहन प्रणाली, बेहद उच्च सटीक रिंग लेजर गायरो आधारित इनर्शियल नैविगेशन सिस्टम (आरआईएनएस) और अत्याधुनिक सटीक आकलन करने वाले माइक्रो नैविगेशन सिस्टम (एमआईएनएस) से यह सुनिश्चित हुआ कि मिसाइल सटीक दूरी के कुछ ही मीटर के भीतर अपने लक्ष्य बिंदु तक पहुंच गई।

स्रोतः द हिंदू

भारत में ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबन्ध प्रभावी

चर्चा में क्यों?

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुधारु पशुओं से दूध निकालने के लिए देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली आक्सीटॉक्सीन दवा के निजी क्षेत्र में निर्माण पर एक जुलाई से रोक लगा दी है. साथ ही विदेश से भी इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- निजी क्षेत्र के दवा निर्माताओं को घरेलू उपयोग के लिए एक जुलाई से आक्सीटॉक्सीन के उत्पादन की इजाजत नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्वीटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) घरेलू उपयोग के लिए इस दवा को तैयार करेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य

- ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2018 से प्रभावी हो जाएगा. ऑक्सीटोसिन का आयात पहले से ही प्रतिबंधित है।
- एक जुलाई से कोई भी कंपनी घरेलू इसे उपयोग करने के लिए इस दवा का उत्पादन नहीं कर सकेगी।
- ऑक्सीटोसिन आमतौर पर डेयरी उद्योग में दुधारू पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है।
- कर्नाटक स्थित एंटी बायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (के एपीएल) इस दवा का निर्माण करेगा लेकिन बाकी कंपनियों के लिए इसका निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।

ऑक्सीटोसिन का उपयोग

- ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का उपयोग आमतौर पर दूध देने वाले पशुओं पर अतिरिक्त दूध देने के लिए किया जाता है।
- इसका इंजेक्शन लगा देने से पशु किसी भी समय दूध दे सकता है. यह स्वत: उत्पन्न होने वाला हार्मोन है जो कि गर्भाशय के संकुचन का कारण बनता है।
- इसके उपयोग से पशुओं में प्राकृतिक क्षमता कम होती है तथा दूध की गुणवत्ता में भी कमी आती है।
- वर्तमान समय में इसका उपयोग खेती में भी किया जा रहा है. आमतौर पर कद्दू, तरबूज, बैंगन, खीरा आदि का आकार बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
- इससे सब्जियों का आकार रातों-रात बढ़ाया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पंजीकृत अस्पतालों और चिकित्सालयों को सलाह दी है कि वे ऑक्सीटॉसिन खरीदने के लिए केवल केएपीएल से संपर्क कर अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। यह दवा अब किसी और रिटेल स्टोर पर नहीं मिलेगी। इसकी बिक्री किसी अन्य नाम या किसी अन्य कम्पनी द्वारा किए जाने पर उचित कारवाई की जाएगी।

स्रोत: द हिंदू

सांगली की हल्दी को जीआई टैग हासिल हुआ

चर्चा में क्यों?

☞ महाराष्ट्र स्थित सांगली की हल्दी को भारतीय पेटेंट कार्यालय से 27 जून 2018 को ज्योग्राफिकल इंडेक्स (जीआई) रैंकिंग प्रदान की। सांगली में हल्दी की खेती करने वाले किसान लंबे समय से सांगली ची हलद यानी सांगली की हल्दी को जीआई टैग देने की मांग कर रहे थे।

मुख्य तथ्य :

- ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व सांगली के किसानों ने हल्दी उत्पादन एवं इसके भण्डारण के लिए एक विशेष तरीका खोजा था।
- वे हल्दी को जमीन के नीचे गहरे तक दबा देते थे जिससे हल्दी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी और वह जल्दी खराब नहीं होती थी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस देसी तकनीक से जहां हल्दी की पैदावार बढ़ी वहीं इसके स्वाद एवं गुणवत्ता के कारण यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई।
- यह फसल यहां के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।

सांगली के बारे में

- सांगली महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख शहरों में से एक शहर है। सांगली शहर दक्षिण-पश्चिम भारत के पश्चिम एवं दक्षिण महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सांगली-पुणे-बैंगलोर रेलमार्ग पर कोल्हापुर के पूर्व में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। यह शहर भूतपूर्व सांगली राज्य (1761-1947) की राजधानी था। सांगली संस्थान के वर्तमान राजा विजयसिंहराजे पटवर्धन हैं।
- सांगली के आसपास का इलाका कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ज्वार, गेहूँ और दलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। सांगली की हल्दी की फसल पूरे देश के व्यापक बाजार पर नियंत्रण रखती है। इस क्षेत्र की विशेषता यहाँ के अंगूर भी हैं, जिसका एक बड़ा बाजार है। गन्ना मुख्य सिंचित फसल है, जिसने अनेक स्थानों की चीनी मिलों की उन्नति में सहायता की है।

जीआई टैग क्या है?

- भौगोलिक संकेतक (Geographical indicator&GI) किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है।
- जीआई टैग उसी उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है यहाँ उस उत्पाद का वहां की भौगोलिक ईकाई से विशेष जुड़ाव हो।
- जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनले मूल्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है।
- यह संकेत प्राप्त होने पर उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता सुनिश्चित होती है।
- भौगोलिक संकेत का टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है क्योंकि उत्पाद की विशेषता और उसके अन्य गुण उसके उत्पति स्थान के कारण ही होते हैं।
- यह दर्शाता है कि वह उत्पाद एक विशिष्ट क्षेत्र से आता है। यह टैग किसानों और विनिर्माताओं को अच्छे बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है।
- जीआई टैग प्राप्त कुछ उत्पाद हैं- कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, इत्यादि।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी

चर्चा में क्यों?

☞ केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 19 जून 2018 राष्ट्रीय पठन-पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की।

मुख्य तथ्य :

- सूचना व संचार तकनीक (एनएमईआरसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है।
- एनडीएल का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है।
- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी भारत तथा विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री एकत्र करने का एक प्लेटफॉर्म है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय है, जिसमें पाठ्य पुस्तक, निबंध, वीडियो-आडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है।
- कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय और कहीं से भी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है. यह सेवा निःशुल्क है।

विशेषताएं

- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट के लिए www-ndl-gov-in पर विजिट कर सकते हैं।
- वेबसाइट के अलावा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी मोबाइल एप्प पर भी उपलब्ध है।
- यह मोबाइल एप्प पूरे देश के पुस्तकालयों और यहां तक कि विदेशी पुस्तकालयों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता है।
- यह एप्प आईफोन और एंड्रायड दोनों में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- उपयोगकर्ता विषय, स्रोत, सामग्री का प्रकार आदि के माध्यम से विषय वस्तु ढूंढ सकते हैं।
- अभी यह एप्प तीन भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला में उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन हो चुका है तथा सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष इस संख्या में 10 गुनी वृद्धि करना है।

स्रोतः पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नया रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

☞ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जून 2018 को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश के पहले एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र का लोकार्पण किया।

☞ इसके साथ, नया रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र अब भारत में परिचालित होने वाला 10वां स्मार्ट सिटी सेंटर बन गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित 9 अन्य शहर:

☞ महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, नौ शहरों में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, पुणे, नागपुर, राजकोट, विशाखापत्तनम, भोपाल और काकीनाडा में परिचालित है।

नया रायपुर स्मार्ट सिटी :

❑ यह केन्द्र नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के अनुरुप स्थापित किया गया है।

❑ नया रायपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए छत्तीसगढ़ के 3 स्मार्ट शहरों में से एक है, अन्य दो शहर रायपुर और बिलासपुर हैं।

❑ नया रायपुर को सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वित्त, व्यापार, आतिथ्य, चिकित्सा और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में एक सेवा केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।

❑ नया रायपुर भारत का पहला स्मार्ट ग्रीनफील्ड शहर भी है और यह देश के पहले स्मार्ट शहर में भी डिजिटल रूप से सुलभ है।

एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र के फायदे :

❑ एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र से नया रायपुर शहर में इस एक ही स्थान से ई-गवर्नेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और यूटीलिटी मैनेजमेंट जैसे कार्य नियंत्रित किए जाएंगे।

❑ यह पूरी तरह से स्वचालित केन्द्र है।

❑ इस केन्द्र से नया रायपुर शहर के भवनों में बिजली और पानी के वितरण, ए.सी. सिस्टम के नियंत्रण और लिफ्ट परिचालन को नियंत्रित किया जा सकेगा।

❑ इस सिस्टम के तहत नया रायपुर शहर में उच्च गुणवत्ता के सौ से अधिक कैमरे लगाए गए हैं।

❑ इस केन्द्र से विभिन्न नागरिक सेवाएं और स्वीकृतियां ऑनलाइन प्रदान करने में आसानी होगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यह केन्द्र जी.आई.एस. प्लेट फॉर्म की सहायता से संचालित किया जाएगा।
- नया रायपुर स्मार्ट सिटी के नागरिक इस केन्द्र में बिजली, पानी आदि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अपनी शिकायत वहां के हेल्प लाइन नंबरों पर दर्ज करवा सकते है।
- इस केन्द्र के माध्यम से नया रायपुर शहर में आने और बाहर जाने वाले वाहनों के नंबर, वाहन की गति और उसकी लोकेशन की जानकारी मिलेगी।
- इससे यातायात को सुचारू बनाना आसान होगा।

स्रोतः द हिंदू

3000 अतिरिक्त अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

☞ नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने 12 जून 2018 को अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना के लिए 3,000 अतिरिक्त स्कूलों का चयन किया है. इसके साथ ही एटीएल स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 5,441 हो जाएगी।

उद्देश्यः

- भारत के प्रत्येक जिले में एटीएल की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य नवाचार परितंत्र को स्थापित करना है। इससे प्रौद्योगिकी नवाचार और शिक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएगा।

मुख्य तथ्यः

- चयनित स्कूलों को देश भर में माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता भावना बढ़ाने हेतु अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिए अगले पांच वर्षों में बतौर अनुदान 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- ये 3,000 अतिरिक्त स्कूल एटीएल कार्यक्रम की पहुंच को काफी हद तक बढ़ा देंगे जिससे और ज्यादा संख्या में बच्चे टिंकरिंग एवं नवाचार से अवगत हो सकेंगे।
- भारत के युवा अन्वेषकों की पहुंच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कि 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और माइक्रोप्रोसेसर तक सुनिश्चित हो जाएगी।
- इन अतिरिक्त एटीएल स्कूलों से वर्ष 2020 तक 10 लाख से भी ज्यादा आधुनिक बाल अन्वेषकों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) :

- अटल टिंकरिंग लैब का लक्ष्य कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों में लैब की स्थापना करना हैं।
- ये एटीएल इन विद्यार्थी अन्वेषकों के लिए नवाचार हब (केन्द्र) के रूप में कार्य करेंगी जिससे उन्हें उन अनूठी स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में आसानी होगी जिनका सामना उन्हें अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है।
- नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के तहत एटीएल पहल द्वारा सृजित उस सहयोगात्मक परितंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक और औद्योगिक भागीदार नवाचार को बढ़ावा देंगे और आज के उन बच्चों में वैज्ञानिक समझ एवं उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए कार्य करेंगे जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक उल्लेखनीय योगदान करेंगे।
- इन नव चयनित स्कूलों से उन सभी औपचारिकताओं के संबंध में शीघ्र ही संपर्क स्थापित किया जाएगा जो उन्हें अनुदान प्राप्त करने और अपने-अपने परिसरों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिए पूरी करनी हैं।

अटल नवाचार मिशन

- अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है।
- एआईएम का उद्देश्य देश में नवाचार परितंत्र पर नजर रखना और नवाचार परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक छत्र या बृहद संरचना को सृजित करना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए समूचे नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके।
- अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज (एटीएल) अन्वेषकों और अटल इन्क्यूबेशन केन्द्रों का सृजन करने के साथ-साथ पहले से ही स्थापित इन्क्यूबेशन केन्द्रों को आवश्यक सहायता मुहैया कराती है, ताकि नवाचारों को बाजार में उपलब्ध कराना और इन नवाचारों से जुड़े उद्यमों की स्थापना करना सुनिश्चित हो सके।
- इन नए अतिरिक्त एटीएल स्कूलों की स्थापना के साथ ही एटीएल स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 5,441 हो जाएगी जो सभी राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों में से पांच केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अमेरिकी सरकार ने छह लड़ाकू अपाचे हेलिकॉप्टर की खरीद को मंजूरी प्रदान की

चर्चा में क्यों?

☞ अमेरिकी संसद ने 12 जून 2018 को भारत द्वारा छह लड़ाकू अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदे जाने की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार द्वारा इस खरीद के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

☞ यह हेलीकॉप्टर एक मिनट में 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर निशाना साधने में सक्षम है। पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गई थी। सेना को पहली बार ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलेंगे।

अपाचे हेलिकॉप्टर की विशेषताएं

- अपाचे को वर्ष 1981 तक एएच-64 नाम से जाना जाता था. इसे 1981 के अंत में अपाचे नाम दिया गया।
- अमेरिकी सेना उस समय तक अपने हेलीकॉप्टिरों का नाम अमेरिकी भारतीय जनजातीय नामों पर रखती थी। अप्रैल 1986 में अपाचे को अमेरिकी सेना में शामिल किया गया।
- अपाचे में लगे सेंसर की सहायता से यह अपने दुश्मनों को ढूंढ कर उन्हें समाप्त कर सकता है।
- अपाचे में लगे नाइट विजन सिस्टम से इसे रात में काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती।
- इसमें लगाई गई 30 मिलिमीटर की एक एम230 चेन गन को मेन लैंडिंग गियर के बीच इंस्टॉमल किया गया है जिससे यह हेलिकॉप्टर की मारक क्षमता को दोगुना करती है।
- अपाचे हेलीकॉप्टर में एजीएम-114 हेलीफायर मिसाइल लगे हैं और हाइड्रा 70 रॉकेट पॉड्स भी लगे हैं।
- यह हेलीकॉप्टर 293 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ सकता है. अपाचे की लंबाई 18 मीटर है तथा इसमें टर्बोसाफ्ट इंजन लगे है। इसका वजन 5,165 किलो है।

पृष्ठभूमि

- भारत में मिग-35 की जगह पर हमलावर अपाचे हेलीकॉप्टर को लाया जा रहा है. लेकिन, अपाचे हेलीकॉप्टर के नियंत्रण को लेकर भारतीय वायुसेना के साथ लंबा गतिरोध बना रहा था।
- सितंबर 2015 में सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए बोइंग के 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी दे दी।
- उस वक्त केन्द्र सरकार ने यह कहा था कि थल सेना के लिए इस हेलीकॉप्टर की खरीद की जाएगी। लेकिन, उसकी डील में लगातार देरी होती चली गई। अब जाकर यह डील दोनों देशों द्वारा अंतिम रूप ले सकी है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन भारत की जीडीपी को प्रभावित कर सकता है: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

☞ विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी भारी पड़ सकता है और इसके चलते 2050 तक उसकी जीडीपी को 2.8 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है।

☞ रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण तीन दशकों में वायुमंडल के औसत सालाना तापमान में 1-2 डिग्री की तेजी आने का अनुमान है।

☞ जलवायु परिवर्तन में यह बदलाव वर्ष 2050 तक भारत की लगभग आधी जनसंख्या के जीवन स्तर को भी प्रभावित कर सकता है।

मुख्य तथ्य:

❑ रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और मानसूनी बारिश के बदलते प्रतिमान की कीमत भारत को जीडीपी में 2.8 प्रतिशत कमी के रूप में चुकानी पड़ेगी। इससे वर्ष 2050 तक देश की लगभग आधी आबादी का जीवन स्तर प्रभावित होगा।

❑ रिपोर्ट के मुताबिक, इसका असर देश की करीब 60 करोड़ आबादी पर पड़ेगा। वहीं इसकी सबसे ज्यादा मार कृषि क्षेत्र पर पड़ेगी, जिसकी उत्पादकता में काफी गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा।

❑ इसकी चपेट में आने वाले दस सबसे प्रभावित जिलों में महाराष्ट्र के सात, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव एवं दुर्ग और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद होगा। यह सभी जिले अगले 32 सालों में देश के सबसे गरम स्थान होंगे।

❑ विश्व बैंक ने भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों को इसे लेकर उस समय सतर्क किया है, जब अकेले भारत के तापमान में सालाना डेढ़ से दो डिग्री तक की बढ़ोतरी हो रही है।

❑ जलवायु परिवर्तन के चलते जीवन स्तर में होने वाले इन बदलावों का आकलन भारत में लोगों के वर्ष 2010 में रहन-सहन के स्तर और अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाली खपत को आधार बनाकर किया गया है।

❑ विश्व बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में वर्ष 2050 तक तापमान में सालाना एक से दो डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। इससे कृषि, श्रम क्षेत्र और छोटे उद्योगों पर असर पडने के कारण किसानों, श्रमिकों और छोटे कारोबारियों सहित भारत की लगभग आधी आबादी के जीवन स्तर में गिरावट आएगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

समाधान हेतु सुझाए गए उपाय:

- रिपोर्ट में समस्या के तात्कालिक समाधान के तौर पर भारत के लिए तीन उपाय सुझाए हैं। इनमें जलसंकट का स्थाई उपाय खोजना, गैरकृषि रोजगारों को बढ़ावा देना तथा शिक्षा के प्रसार की मदद से लोगों को जलवायु परिवर्तन के संकट के प्रति आगाह करते हुये जागरूक करना शामिल है।
- भारत में उन इलाकों में रोजगार के वैकल्पिक तरीकों का प्रसार करना होगा जिनमें खेतीयोग्य जमीन की अनुपलब्धता है या जिनमें अभी भी अनुपजाऊ जमीन पर पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही है।
- प्रभावित जिलों में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा सहित अन्य आधारभूत ढांचागत मौलिक सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया है।

विश्व बैंक:

- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है।
- विश्व बैंक समूह पांच अन्तर राष्ट्रीय संगठनो का एक ऐसा समूह है जो देशो को वित्त और वित्तीय सलाह देता है।
- विश्व बैंक समूह के मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है।
- विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमरीका के ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं के एक सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थ व्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थ व्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है।
- विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर भारत की मानसून प्रणाली में बदलाव आया है वहीं दूसरी ओर देश की कृषि व्यवस्था भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है. निरंतर सूखे एवं बाढ़ की समस्या से त्रस्त भारतीय किसानों के समक्ष आजीविका का संकट देश की अर्थव्यवस्था में गंभीर चुनौती बन गया है।
- तापमान में बढ़ोतरी की वजह से जलवायु परिवर्तन के कारण जीवन स्तर में बदलाव की भयावह तस्वीर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगी।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

स्वच्छ भारत मिशन: केंद्र सरकार ने 10 नए स्वच्छ दर्शनीय स्थलों की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

☞ केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 12 जून 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत 'स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस' (एसआईपी) का तीसरा चरण शुरू किया।

☞ मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत दस स्वच्छ दर्शनीय स्थानों को जोड़ा है।

मुख्य तथ्य:

❑ स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के तीसरे चरण का शुभारंभ माणा गांव में किया गया जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के निकट अवस्थित है।

❑ यह गांव अब एक स्वच्छ आइकॉनिक स्थल बन गया है। इस गांव में पौराणिक महत्व के अनेक स्थल हैं, इसलिए वहां बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं।

❑ मंत्रालय ने 26.87 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के साथ माणा गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन से जुड़ी चार प्रमुख गतिविधियों की भी शुरुआत की जिनमें सामुदायिक सोख गड्ढे एवं खाद (कम्पोस्ट) के गड्ढे तैयार करना, जैव एवं कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट को अलग-अलग करने वाले केन्द्र की स्थापना करना और तरल अपशिष्ट के लिए नालियां बनाना शामिल हैं।

❑ ये नए स्थल अब चरण - और चरण - के तहत चयनित किए गए उन 20 आइकॉनिक स्थलों में सम्मिलित हो गए हैं जहां विशेष स्वच्छता या साफ-सफाई के कार्य पहले से ही जारी हैं।

दस स्वच्छ दर्शनीय स्थान :

स्वच्छ दर्शनीय स्थान	स्थान	राज्य
राघवेंद्र स्वामी मंदिर	कुरनूल	आंध्र प्रदेश
हजारद्वारी पैलेस	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
ब्रहम सरोवर मंदिर	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
विदुर कुटी	बिजनौर	उत्तर प्रदेश
माणा गांव	चमोली	उत्तराखंड
पांगोंग झील	लेह-लद्दाख	जम्मू-कश्मीर
नागवासुकि मंदिर	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
इमा कीथल /मार्केट	इंफाल	मणिपुर
सबरीमाला मंदिर	पठानमथिट्टा जिला	केरल
कंवआश्रम	कोटद्वार	उत्तराखंड

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

स्वच्छ आइकॉनिक स्थल (एसआईपी)

- प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित यह परियोजना राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समन्वित या संचालित की जा रही है।
- इन नए स्थलों को आवश्यक सहयोग या सहायता प्रदान करने के लिए सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) भागीदारों के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू)/कंपनियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए सलाह-मशविरा फिलहाल जारी है।
- एसआईपी इन तीन अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना है: आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय।
- इसमें संबंधित राज्यों के स्थानीय प्रशासन शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें प्रायोजक भागीदारों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियां भी शामिल हैं।
- पहला चरण वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, जबकि नवंबर 2017 में स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का दूसरा चरण लॉन्च किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है।
- यह अभियान महात्मा गाँधी के जन्मदिवस 02 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया।
- स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है।
- सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौंच मुक्त (ओडीएफ) भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

स्रोतः द हिंदू

केंद्र सरकार बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ मिलकर काम करेगी

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्र सरकार ने बाढ़ के बेहतर पूर्वानुमान के लिए गूगल से साझेदारी की है. देश के शीर्ष तकनीकी संगठन केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने सर्च इंजन गूगल के साथ यह समझौता किया।

मुख्य तथ्य

- इस समझौते के तहत गूगल द्वारा विकसित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान और लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मानचित्रण में उसकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल आयोग द्वारा किया जायेगा।
- इस पहल से संकट प्रबंधन एजेंसियों को जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजिकल) संबंधी समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलने की आशा है।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तैयार करने में गूगल अपने हाई रिजॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल का इस्तेमाल करेगा जबकि केंद्रीय जल आयोग अपनी ओर से जलस्तर, बारिश आदि के नियमित आँकड़े उपलब्ध करायेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इसके जरिये तीन दिन आगे के लिए नदियों के जलस्तर का पूर्वानुमान जारी किया जा सकेगा।
- यह इस वर्ष (2018) पूर्वानुमान परीक्षण के आधार पर जारी किया जायेगा तथा बाद में इसका दायरा विस्तृत करने की योजना है।
- नयी तकनीक से प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े संगठन समय रहते बाढ़ के जोखिम वाले इलाकों तथा आबादी की पहचान कर सकेंगे तथा चेतावनी जारी की जा सकेगी।

उद्देश्य

- समझौते का उद्देश्य बाढ़ के पूर्वानुमान को बेहतर बनाना है जिससे क्षेत्र विशेष के लिए चेतावनी जारी की जा सके.
- साथ ही प्रयोग के तौर पर गूगल अर्थ इंजन का प्रयोग करते हुये बाढ़ प्रबंधन पर निगरानी रखी जायेगा। इसके अलावा गूगल भारत की नदियों पर एक ऑनलाइन प्रदर्शनी भी तैयार करेगा।

महत्व

- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग लंबे समय से बाढ़ आने से पहले समय रहते सटीक चेतावनी दिए जाने की मांग करे रहे थे।
- इस पहल से उनकी यह मांग पूरी होगी. गूगल उच्च स्तरीय डिजिटल, तकनीक जिसमें वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञता के सहारे सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रदत्त जानकारी के सहयोग से बाढ़ की सटीक जानकारी देगा।
- अब संभवत: बाढ़ आने के तीन दिन पहले ही लोगों को जानकारी मिल सकेगी।
- इस समझौते के बाद सरकार को करोड़ों रुपये की बचत होगी। इससे सरकार और आपदा प्रबंधन संगठनों को बाढ़ प्रभावित स्थानों और जनसंख्या की बेहतर जानकारी प्राप्त होगी।
- यह पहल बेहतर बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी।

स्रोत: द हिंदू , डेक्कन क्रॉनिकल

समुद्र में गंदगी के लिए गंगा सहित विश्व की 10 नदियां जिम्मेदार: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि दुनियाभर के समंदरों में मिल रहे कचरे के लिए 10 नदियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इनमें चीन की यांग्त्जे नदी पहले नंबर पर है जो कि चीन की सबसे लंबी नदी है।
- इनमें दूसरे पायदान पर भारत की गंगा नदी है। समंदरों में जो प्लास्टिक कचरा मिल रहा है, उसका करीब 90% इन 10 नदियों से ही आ रहा है। इन 10 नदियों में से 8 एशिया की हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

समुद्र में कचरे के लिए जिम्मेदार 10 नदियां :

1 .	यांग्त्जे, चीन	4.	पर्ल, चीन
2.	गंगा, भारत	5.	एमर रूस, चीन
3.	येलो, चीन	6.	सिंधु, भारत
7.	मिकांग, चीन	8.	है ही, चीन
9.	नील, अफ्रीका	10.	नाइजर, अफ्रीका

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- समुद्र तक प्लास्टिक कचरा ले जाने में गंगा दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि सिंधु छठे स्थान पर आती है।
- शोधकर्ता डॉ. क्रिश्चियन स्कीमिट के अनुसार अधिकतर कचरा नदी के किनारों की वजह से होता है, जिसका निपटारा नहीं हो पाता है और वह बहता हुआ समंदरों में आ जाता है।
- ये भी देखने में आया कि बड़ी नदियों के प्रति घन मीटर पानी में जितना कचरा रहता है, उतना छोटी नदियों में नहीं रहता है।
- कुछ साल पहले सरकार ने गंगा की सफाई के लिए श्नमामि गंगे प्रोजेक्टश शुरू किया था, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हो सकी है।
- एशिया की सबसे लंबी और दुनिया में इकोलॉजी के लिहाज से महत्वपूर्ण नदियों में से एक यांग्त्जे के आसपास चीन की एक तिहाई आबादी यानी 50 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं. यही समंदर में सबसे ज्यादा कचरा ले जा रही है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 80 लाख टन कचरा समंदरों में मिल रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए चीन ने 46 शहरों में कचरे को काबू करने का निर्देश जारी किया है।

स्रोतः द हिंदू

समग्र जल प्रबंधन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग द्वारा 14 जून 2018 को समग्र जल प्रबंध रिपोर्ट जारी की गई. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। जल के उचित प्रबंधन और उपयोग के अभाव में जलसंकट आने वाले वर्षो में और गहराएगा।
- रिपोर्ट के अनुसार स्थिति यह है कि 600 मिलियन लोग गंभीर जलसंकट का सामना कर रहे हैं और 2,00,000 लोगों की प्रतिवर्ष शुद्ध जल के अभाव में मृत्यु हो जाती है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

समग्र जल प्रबंधन रिपोर्ट: मुख्य तथ्य

- रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत में जल की मांग आपूर्ति से दोगुना होने का अनुमान है, जिसके कारण लाखों लोगों को गंभीर जलसंकट झेलना पड़ेगा।
- नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन के पहले सूचकांक के आधार पर राज्यों की सूची तैयार की है।
- यह सूचकांक नौ व्यापक क्षेत्रों में भूमिगत , जल निकायों के स्तर में सुधार , सिंचाई, कृषि गतिविधियां, पेय जल, नीति एवं संचालन व्यवस्था समेत कुल 28 विभिन्न संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है।
- वर्ष 2015-16 के मुकाबले सुधार के मामले में सामान्य राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर रहा जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है।
- नीति आयोग ने भविष्य में सालाना आधार पर रैंकिंग जारी करने का प्रस्ताव किया है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के गांवों में 84 प्रतिशत आबादी जलापूर्ति से वंचित हैं जिन्हें पानी मिल रहा है, उसमें 70 प्रतिशत प्रदूषित हैं।
- स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा जुटाए डाटा का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि करीब 70 प्रतिशत प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पर है।

सबसे बेहतर 5 राज्य	सबसे खराब 5 राज्य
गुजरात	झारखंड
हरियाणा	मध्य प्रदेश
आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश
कर्नाटक	बिहार
महाराष्ट्र	ओडिशा

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

- नीति आयोग द्वारा जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में प्रदर्शन का आकलन और सुधार करने के लिए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को उपयोगी उपकरण के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीतियों को तैयार करना और लागू करना है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक में 9 पैरामीटर और 28 संकेतक शामिल हैं।
- इनमें भूजल, सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, कृषि प्रथाओं, पेयजल, नीति और शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
- विश्लेषण के उद्देश्य से सूचकांक में राज्यों को उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्यों और अन्य राज्यों के दो विशेष समूहों में विभाजित किया गया था।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विश्व महासागर दिवस

चर्चा में क्यों?

☞ विश्व महासागर दिवस विश्वभर में 08 जून 2018 को मनाया गया है. महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है।

मुख्य तथ्य

- महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण के वजह से महासागर धीरे-धीरे अपशिष्ट होते जा रहे हैं. इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. वे गलती से प्लास्टिक को अपना भोजन समझ लेते हैं जिससे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।
- विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्त्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है।
- इसका उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में महासागरों के महत्व के बारे में बताना है. इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं, जैसे - खाद्य सुरक्षा, जैव-विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है।
- प्रत्येक वर्ष 'विश्व महासागर दिवस' पर पूरे विश्व में महासागर से जुड़े विषयों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जो महासागर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं.
- महासागर पृथ्वी के लिए फेफड़ों के समान है जहां से संपूर्ण पृथ्वी को अधिकतर ऑक्सीजन प्राप्त होता है. लोगों को समुद्र में फैलाये जा रहे प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बताना. महासागरों के प्रति विश्व भर में जागरुकता फैलाना हैं. समुद्र भोजन एवं दवाओं का सबसे बड़ा स्रोत है इसलिए इसके संरक्षण के उपायों के बारे में लोगों को बताना हैं.
- हमारी पृथ्वी का लगभग 70 प्रतिशत भाग महासागरों से घिरा है। महासागरों में पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का लगभग 97 प्रतिशत जल समाया हुआ है।

पृष्ठभूमि :

- प्रथम विश्व महासागर दिवस 08 जून 2009 को मनाया गया था। यह दिवस वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए 'पृथ्वी ग्रह' नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद मनाया जाने लगा। यह दिन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष महासागरों की वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर देता है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक: भारत 177वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

☞ पर्यावरण दिवस पर 05 जून 2018 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) की रेटिंग जारी की गई. इसमें भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि सूचकांक में शामिल कुल देशों की संख्या 180 है।

☞ वर्ष 2016 में भारत इस सूची में 141वें स्थान पर था. भारत सरकार द्वारा विभिन्न पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम आरंभ किए जाने के बावजूद यह रैंकिंग चिंताजनक है. विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रैंकिंग प्रतिवर्ष जारी की जाती है।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई):

प्रमुख तथ्य

- इस रिपोर्ट में 10 श्रेणियों के अलग-अलग 24 मुद्दों पर रिसर्च की गई है जिसमें वायु की गुणवत्ता, जल एवं स्वच्छता, कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता (जीडीपी के प्रति इकाई उत्सर्जन), जंगलों (वनों की कटाई) और अपशिष्ट जल उपचार शामिल हैं।
- इस रिपोर्ट को डब्ल्यूईएफ के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है।
- रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि से विकास पर प्रभाव पड़ने की भी बात कही गई है तथा इस रिपोर्ट में चीन को 120वां स्थान दिया गया है।
- ईपीआई में पाकिस्तान को भारत से बेहतर 169वां स्थान दिया गया है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को 27वें स्थान पर रखा गया है।
- इस सूची में स्विटजरलैंड शीर्ष स्थान पर है जबकि फ्रांस दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है।

भारत के संदर्भ में

- भारत सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में काफी दूर है. इसमें भारत 157 देशों में से 116वें स्थान पर है।
- ईपीआई आंकड़ों में कहा गया है कि भारत में गरीबी का बना रहना भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है।
- भारत में प्रति 10 लोगों में से 6 लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं. यह लोग प्रतिदिन 3.20 अमेरिकी डॉलर से भी कम खर्च पर जीवनयापन करते हैं।
- भारत के आधे से अधिक किसान कर्ज में डूबे हैं।
- भारत में पिछले एक दशक में 64 प्रतिशत खाद्यान्न आयात किये गये हैं।
- वायु की गुणवत्ता को 100 में से 5.75 अंक दिए गये हैं।
- भारत के 82 प्रतिशत ग्रामीण लोग बिना नल के पानी के अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

☞ मौजूदा हालात में सतत विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में निवेश करना भी आवश्यक है। साथ ही ओद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण का सावधानीपूर्वक प्रबन्धन भी मायने रखता है, जो प्रदूषण पैदा कर आम जनता एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए घातक परिणाम पैदा करता है।

स्रोतः द हिंदू

विश्व पर्यावरण दिवस : 2018

चर्चा में क्यों?

☞ विश्व भर में 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रत्येक विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथक आयोजक देश का चयन होता है जहां आधिकारिक समारोह का आयोजन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की वैश्विक मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है।

☞ पहला विश्व पर्यावरण दिवस5 जून 1974 को मनाया गया था।

विश्व पर्यावरण दिवस के थीम और उद्देश्य

❑ प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

❑ विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम- 'बीट प्लास्टिक पोल्यूशन' यानी प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना।

❑ इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरुक करना तथा पर्यावरण के लिए कार्य करना है।

प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण:

❑ इस साल आयोजन की थीम प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण से मुक्ति का संकल्प लेना है. पैकेजिंग उद्योग सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा उत्पादित करते हैं. इनमें बोतल, कैप, खाने के पैकेट, प्लास्टिक बैग आदि शामिल हैं।

❑ एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्र को प्रदूषित करने वाले शीर्ष पांच प्रदूषकों में चार दूषित तत्व पैकेंजिंग उद्योग से निकलने वाले प्लास्टिक उत्पाद हैं। भारत में 24,940 टन प्लास्टिक कचरा प्रतिदिन निकलता है. इसमें 60 प्रतिशत कचरे का ही निस्तारण हो पाता है. शेष 40 प्रतिशत कचरे का निस्तारण पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास :

❑ संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके दो साल बाद, 5 जून 1974 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। वर्ष 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग - अलग देशों को चुना जाता है. इसमें प्रत्येक साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय नौसेना :

- भारतीय नौसेना विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने हरित पहल कार्यक्रमों के चार वर्ष पूरा कर रही है। भारतीय नौसेना ने पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा दक्ष प्रणाली की दिशा में कई नीतियां बनाकर लागू की है। इसके परिणामस्वरूप सभी नौसैनिक अड्डों पर बेहतर परिणाम हासिल हुये हैं। नौसेना ने 'भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोडमैप' को अपनाया है, जिसके तहत नौसेना अपनी समुद्री क्षमताओं में पर्यावरण को ध्यान रखते हुए वृद्धि कर रही है।
- नौसेना ने 16,000 की संख्या में वृक्षारोपण किया है, जिससे अनुमानित तौर पर 324 टन कार्बन डाई ऑक्साइड कम होगी। नौसैनिक अड्डो पर ऊर्जा की खपत कम हो, इसके लिए समय-समय पर ऑडिट की जा रही है।

स्रोतः द हिंदू

ELITE IAS

अन्य खबरें

12वां सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया

☞ सांख्यिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पी. सी. महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है।

☞ यह दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है. सांख्यिकी दिवस देशभर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य सरकार, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, विश्वविद्यालय/विभाग आदि में सम्मेलन, वाद-विवाद, क्विज कार्यक्रम, निबंधन प्रतियोगिता आदि के माध्यम से मनाया जाता है।

लुईस हैमिल्टन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता

☞ मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हेमिल्टन ने 24 जून 2018 को फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब जीता. लुईस हैमिल्टन ने ड्राइवरों की विश्व चौम्पियनशिप तालिका में अपनी बढ़त मजबूत कर ली. इस प्रतियोगिता में रेड बुल के मैक्स वस्टापेन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तीसरा स्थान फरारी के किमी राइकोनेने को मिला।

लुईस हेमिल्टन ने एक घंटे 30 मिनट 11.385 सेकेंड में रेस पूरी की. मैक्स वस्टापेन उनसे 7.090 सेकेंड पीछे रहे जबिक किमी राइकोनेने 25.888 सेकेंड पीछे रहते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।

नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस

☞ विश्व भर में 26 जून 2018 को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय है: पहले सुनें

उद्देश्य

☞ इस दिवस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं से मुक्ति पाना है तथा समाज में सशक्तिकरण लाना है। इस दिन विभिन्न संगठन इस खतरे को खत्म करने के लिए शपथ लेते हैं और अवैध ड्रग्स की चुनौतियों को शांतिपूर्वक संबोधित करने पर जोर देते हैं। उनका मूल सिद्धांत युवाओं की रक्षा करना और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देना है।

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और क्राइम कार्यालय (यूएनओडीसी) :

☞ संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और क्राइम कार्यालय (यूएनओडीसी) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग और उसके उत्पादन के खिलाफ लड़ रहा है जिसे एक अंतरराष्ट्रीय अपराध माना जाता है। वर्ष 1997 में इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपराध निवारण केंद्र में विलय करके स्थापित किया गया था।

☞ संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम पर दुनिया भर में चल रहा है। अवैध नशीली दवाओं की तस्करी, अपराध दर में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सदस्यों की सहायता करने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और क्राइम कार्यालय अनिवार्य है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव :

☞ 7 दिसम्बर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा प्रस्ताव 42/112 द्वारा 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाये जाने की घोषणा की गयी।

☞ इस प्रस्ताव से 1987 के नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भी मजबूती प्राप्त हुई।

अनुकृति वास ने जीता मिस इंडिया 2018 का खिताब

☞ तमिलनाडु की अनुकृति वास ने 19 जून 2018 को 'फेमिना मिस इंडिया 2018' का खिताब जीता. अनुकृति वास ने 29 प्रतियोगियों को हरा कर इस खिताब को जीता। इस प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अनुकृति वास को ताज पहनाया। अनुकृति वास इससे पहले मिस तमिलनाडू 2018 का खिताब जीता था। मुंबई में आयोजित हुए इस कॉन्टेस्ट में हरियाणा की रहने वाली मीनाक्षी चौधरी फर्स्ट रनर-अप बनीं और सेकेंड रनर-अप आंध्र प्रदेश की रहने वाली श्रेया राव बनीं। वहीं दिल्ली की रहने वाली गायत्री भारद्वाज, झारखंड की रहने वाली स्टेफी पटेल टॉप 5 में शामिल थीं।

विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2018 मनाया गया

☞ विश्व भर में 21 जून 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया. इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 (International Yoga Day 2018) का थीम- शांति के लिए योग हैं. इस दिन, जो मानव शरीर के आंतरिक और बाहरी कल्याण के लिए समर्पित है, दुनिया भर के लोग समूहों में योग का अभ्यास करते हैं।

☞ चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में स्थापित वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में योग किया। पीएम के साथ करीब 55 हजार लोगों ने योग किया।

इवान ड्यूक कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित

☞ दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 17 जून 2018 को संपन्न राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के उम्मीदवार इवान ड्यूक ने जीत हासिल की. वे कोलंबिया के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं।

☞ इवान को करीब 54% वोट हासिल हुए जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी गुस्तावो पेट्रो को 41.8% वोट मिले. इवान ने यह चुनाव कोलंबियाई गृहयुद्ध में गोरिल्ला विद्रोहियों के खिलाफ हुए शांति समझौते में बदलाव करने को लेकर लड़ा था। ड्यूक को कोलंबिया की अर्थव्यवस्था के लिए हितैषी माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान टैक्स में कटौती तथा निवेश में बढ़ोतरी के लिए कहा था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विश्व रक्तदान दिवस

- पूरी दुनिया में 14 जून 2018 को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है।
- इस दिन जागरूकता अभियान चलाया जाता है और लोगों को मुफ्त रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है. विश्व रक्तदान दिवस 2018 का थीम- "बी देयर फॉर समवन एल्स. गिभ ब्लड. शेयर लाइफ." (Be there for someone else- Give blood- Share life)।

विश्व रक्तदान दिवस :

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1997 से प्रत्येक वर्ष 14 जून को 'विश्व रक्तदान दिवस' मनाया जाता है. वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100 फीसदी स्वैच्छिक रक्तदान नीति की नींव डाली थी।
- इसके अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह लक्ष्य रखा था कि विश्व के प्रमुख 124 देश अपने यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दें।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि रक्त की जरूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े। अबतक विश्व के लगभग 49 देशों ने ही इस पर अमल किया है।

14 जून ही रक्तदान दिवस क्यों?

- महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाईन का जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। उन्होंने मानव रक्त में उपस्थित एग्ल्युटिनिन की मौजूदगी के आधार पर रक्तकणों का ए, बी और ओ समूह में वर्गीकरण किया। इस वर्गीकरण ने चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी इसी खोज से आज करोड़ों से ज्यादा रक्तदान रोजाना होते हैं और लाखों की जिंदगियां बचाई जाती हैं। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए ही कार्ल लैंडस्टाईन को वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार दिया गया था।

अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस: 2018

- विश्व भर में 12 जून 2018 को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया. इसका उद्देश्य बाल श्रम के विरुद्ध लोगों में जागरुकता फैलाना है।

विषय: सुरक्षित और स्वस्थ पीढ़ी

- इस वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल दिवस दोनों एक साथ मनाये जा रहे हैं। इससे लोगों को सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों की जागरुकता फैलाई जा सकेगी ताकि कामकाजी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे तथा बाल श्रम समाप्त हो सके।
- इस संयुक्त अभियान का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 8.8 के अनुसार 2030 सभी को सुरक्षित कामकाजी स्थल उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार सतत विकास लक्ष्य 8.7 के अनुसार 2025 तक किसी भी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त किया जायेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- एक बार इन लक्ष्यों की प्राप्त होने पर इनका लाभ अगली पीढ़ी को मिल सकेगा तथा उनमें भी कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं बालश्रम के विरोध में भावना को बल मिलेगा।
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने बाल श्रम की समाप्ति की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की घोषणा की।
- तभी से बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जगरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है।

राफेल नडाल ने 11वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता

- विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर खिताब जीता. नडाल ने थिएम को लगातार सेटों में 6-4, 6-3, 6-2 से हराकर 11वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता. स्पेन के 32 वर्षीय खिलाड़ी राफेल नडाल का यह 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब है. टेनिस के इतिहास में 11 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले नडाल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

महेश कुमार जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त

- यह नियुक्ति वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति समिति द्वारा की गई है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर, वित्तीय सेवाओं के सचिव के अलावा अन्य स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं।
- महेश कुमार जैन के पास 30 वर्ष बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का वृहद अनुभव है।
- इस पद के लिए चयनित होने तक वे मार्च 2017 से आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक पद पर कार्यरत रहे।
- इससे पहले नवंबर 2015 में उन्हें इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।
- जैन बैंकिंग क्षेत्र की कई समितियों में भी शामिल रहे हैं जिनमें बसंत सेठ समिति प्रमुख है।